मनदीप कौर, न्यूज़ एडीटर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 16-30 NOVEMBER 2025

मुल्य : 5 रुपए

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

जीडीपी ग्रोथ पर पीएम मोदी ने जताई खुशी

कहा– 8.2 प्रतिशत रहना उत्साहजनक, सुधारों को आगे बढ़ाते रहेंगे

नई दिल्ली (एजंसी)–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को बताती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के दम पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर जुलाई–सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत रही है, जो पिछली छह तिमाहियों में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स% पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर बहुत उत्साहजनक है। यह हमारी वृद्धि–समर्थक नीतियों और सुधारों के प्रभाव को बताती है। यह हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता को भी दर्शाती है। हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए काम करती रहेगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डाक्टरों को सूचीबद्ध करने की सहमति दी

लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए उठाया कदम

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, पंजाब भर के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 12 प्रमुख श्रेणियों के 300 स्पेशलिस्ट डाक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है।

यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण श्रेणियों अर्थात मैडीसिन, पीडियाट्रिक्स (बाल रोग विशेषज्ञ), साइकियाट्री (मनोरोग विशेषज्ञ), डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग विशेषज्ञ), चेस्ट एवं टी.बी. (छाती रोग विशेषज्ञ), सर्जरी, गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग विशेषज्ञ), ऑप्थल्मोलॉजी (नेत्र रोग विशेषज्ञ), ई.एन.टी. (कान, नाक, गला विशेषज्ञ) तथा एनेस्थीसियोलॉजी में 300 विशेषज्ञ डाक्टरों को एम्पैनल करने का भी निर्णय लिया है। इस कदम से विशेषज्ञ डाक्टरों की उपलब्धता

बढ़ेगी और पंजाब के लोगों को सकैंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इन विशेषज्ञ डाक्टरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से की जाएगी तथा एम्पैनल हुए डाक्टर ओ.पी.डी., आई.पी.डी., इमरजेंसी, बड़े–छोटे ऑपरेशन तथा अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रति मरीज एम्पैनलमेंट फीस लेने के हकदार होंगे।

पंजाब को–ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 के तहत एकसमान अनुशासनात्मक एवं अपीलीय ढांचे को मंजूरी– कैबिनेट ने पंजाब को–ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 के अंतर्गत नियम 28ए यानी एकसमान अनुशासनात्मक एवं अपीलीय ढांचे को भी मंजूरी दे दी है। इससे अपील चैनलों की दोहरी प्रक्रिया रोकी जा सकेगी, एक ही बोर्ड या उसकी समितियों में परस्पर विरोधी निर्णयों से बचा जा सकेगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में कमांड की स्पष्ट लड़ी बनेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि अपीलों की सुनवाई संस्था के भीतर केवल एक बार ही हो। यह एक स्पष्ट एकसमान ढांचे के तहत उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करके तथा हर स्तर पर प्राधिकार को परिभाषित करके संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करेगा और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में भी मदद करेगा। इससे पंजाब में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सभी शीर्ष संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों में एकरूपता आएगी।

पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन को मंजूरी– मंत्रिमंडल ने खनन सेवाओं को और अधिक कुशल, नागरिक–हितैषी तथा पारदर्शी बनाने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (संशोधन) पॉलिसी 2025 के अनुसार पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन करने की भी अनुमति दे दी है। प्रदेश में आवंटित की जाने वाली क्रशर माइनिंग साइटों तथा भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के माइनिंग लीज धारकों को माइनिंग अधिकारों के आवंटन के लिए मौजूदा पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में इन नए नियमों/संशोधनों को जोड़ने/बदलने की आवश्यकता थी।

कहां हैं इमरान खान... बेटे कासिम ने मांगा 'प्रूफ ऑफ लाइफ'

अदियाला जेल प्रशासन ने किया खंडन

कराची (एजंसी)–पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कथित मौत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। अफगान मीडिया की एक अपुष्ट रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इमरान खान की अदियाला जेल में हत्या कर दी गई। इसके बाद से उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। इसी बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सार्वजनिक तौर पर पिता के जीवित होने का प्रमाण मांगा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता को 845 दिनों से हिरासत में रखा गया है और पिछले छह हफ्तों से उन्हें एक 'डेथ सेल' में पूर्ण एकांतवास में रखा गया है, जहां किसी भी प्रकार की पारिवारिक मुलाकात या संपर्क की अनुमति नहीं दी गई। कासिम ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद इमरान खान की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि परिवार को उनकी स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कासिम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि यदि इमरान खान को कोई नुकसान हुआ तो इसकी पूरी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की होगी। इमरान की बहन अलीमा खानुम ने भी दावा किया कि परिवार को लगातार मुलाकात से रोका जा रहा है।

तरनतारन में अकाली नेता की बेटी कंचनप्रीत की गिरफ्तारी पर देर रात तक हुई सुनवाई

सुबह 4 बजे रिहाई का फैसला

तरनतारन (मनदीप कौर)–जिला अदालत तरनतारन में पूरी रात चली सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने रविवार तड़के कानचनप्रीत कौर को पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। सुबह 4 बजे सुनाया गया फैसला अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर लेकर आया। क्षेत्र के प्रमुख अकाली नेता, जिनमें विरसा सिंह वाल्टोहा भी शामिल थे, कानचनप्रीत के साथ मौजूद रहे। कानचनप्रीत ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई और न्यायपालिका पर अपना विश्वास दोहराया। इससे पहले, उन्हें शुक्रवार को चबल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कानचनप्रीत कौर, शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) नेता सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी हैं,

जिन्होंने हाल ही में तरनतारन विधानसभा उपचुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें विजय नहीं मिली। फिर भी, चुनाव में सुखविंदर का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा और एसएडी दूसरे स्थान पर रही, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की स्थिति मजबूत हुई।

राहुल गांधी ने खड़गे से की मुलाकात, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर की चर्चा

चुनाव में करना पड़ा था बड़ी हार का सामना

नई दिल्ली (एजंसी)–कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। राज्य में इसी महीने हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर गए, जहां उन्होंने बिहार के पार्टी नेताओं से मुलाकात की। बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख राजेश राम भी बैठक में मौजूद थे। इससे पहले, गांधी और खरगे ने बिहार के नेताओं और सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से इंदिरा भवन में मुलाकात की थी, ताकि चुनाव में पार्टी की हार के कारणों का पता लगाया जा सके।

ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्याशियों ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा की गई 10,000 रुपये की प्रोत्साहन योजना की घोषणा, प्रदेश कांग्रेस के भीतर आंतरिक कलह और मतभेद तथा टिकट बंटवारे में देरी को चुनाव में हार की कुछ वजहों के तौर पर गिनाए।

मुख्यमंत्री की ओर से गन्ने का भाव बढ़ाकर 416 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा, पंजाब देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव देने के मामले में अग्रणी

दीनानगर में नई शुगर मिल और को–जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया, राज्य सरकार की ओर से तैयार की जा रही सल्फर रहित फतेह चीनी लॉन्च की

सोनू, रविंदर

दीनानगर, देश भर में गन्ना किसानों को सबसे अधिक भाव देने की परंपरा को बरकरार रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज आगामी पिड़ाई सीजन के लिए गन्ने का भाव बढ़ाकर 416 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है, जो पूरे राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दीनानगर में नई शुगर मिल और को–जनरेशन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब गन्ने का सबसे अधिक भाव देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के किसानों को देश भर में सबसे अधिक भाव देने से किसानों को बड़ा लाभ होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हमेशा से अपने किसानों को देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव देता रहा है और उनकी सरकार ने इसे कायम रखा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस किसान–हितैषी पहल से किसानों, खासकर सीमावर्ती जिलों के किसानों को, जहां गन्ना मुख्य फसल है, बहुत बड़ा फायदा होगा। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि गन्ना फसल विविधीकरण का आधार है, जो राज्य के फसल विविधीकरण प्रयासों को और मजबूत कर सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह गन्ने को पानी की अधिक खपत वाली फसलों का व्यावहारिक विकल्प माने और गन्ने की खेती को अधिकतम प्रोत्साहित करे। मीडिया के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने गुरदासपुर में नई सहकारी शुगर मिल को जनता को समर्पित किया है, जो राज्य के सहकारी और कृषि–औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 1980 में 1,250 टीसीडी की शुरुआती

पिड़ाई क्षमता से शुरू हुई यह मिल 1987 में बढ़ाकर 2,000 टीसीडी की गई थी और यह चार दशकों से अधिक समय से गन्ना उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 80 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन होता है, जबकि पहले मिल की प्रति सीजन पिड़ाई क्षमता केवल 25 लाख क्विंटल थी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इस अंतर को पूरी तरह भरने के लिए इसका बड़े स्तर पर आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई मिल की पिड़ाई क्षमता 5,000 टीसीडी तक बढ़ा दी गई है, जो क्षेत्र में गन्ने की फसल की समय पर और कुशल पिड़ाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि नया शुगर कॉम्प्लेक्स प्रसंस्करण क्षमता और किसानों की आय बढ़ाते हुए गन्ने का सुचारु उपयोग सुनिश्चित करेगा। इससे चीनी की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ परिवहन लागत भी कम होगी। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ–साथ स्थायी राजस्व स्रोत भी पैदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पंजाब के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों की समृद्धि तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि एक अत्याधुनिक सल्फर–रहित रिफाइंड शुगर प्लांट भी स्थापित किया गया है, जो प्रीमियम ग्रेड चीनी उत्पादन करने में सक्षम है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक और प्रमुख विशेषता 28.5 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट का चालू होना है, जिसे पीएसपीसीएल को 20 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिजली निर्यात से प्रत्येक पिड़ाई सीजन के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपए सालाना राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है, जिससे मिल की वित्तीय स्थिरता को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विस्तार से पूरे क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को सीधा लाभ होगा और मिल को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों की संख्या 2,850 से बढ़कर लगभग 7,025 तक पहुंचने की उम्मीद है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे दूर–दराज की निजी मिलों पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी, किसानों का परिवहन समय और लागत काफी घटेगी। स्थानीय मांगों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से चली आ रही मांग जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार पंजाब को मेडिकल क्षेत्र में एक शैक्षणिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने तरनतारन में लड़कियों के लिए एक सरकारी कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दी जा सके। इसके अलावा भगवंत सिंह मान ने कहा कि संपर्क को बेहतर बनाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए जंडियाला गुरु में रेलवे लाइन पर नया ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है। बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले यह सुनिश्चित करें कि हाल के बाढ़ों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा %टोकन राहत% के रूप में घोषित 1,600 करोड़ रुपए की राशि पंजाब को जल्द मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप में शामिल होने के बजाय केंद्र से पंजाब का हक और वैध अधिकार सुरक्षित कराने को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट कहा कि राज्य के अधिकारों के संरक्षक होने के नाते वे चंडीगढ़ या पंजाब यूनिवर्सिटी के दर्जे में बदलाव की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उन्हें जल्द ही सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि गुरदासपुर जिले में कानून–व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और शांति–सद्भाव को खतरे में डालने वाली किसी भी गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की कल्याणकारी पहलों को रेखांकित करते हुए भगवंत सिंह मान ने उल्लेख किया कि पंजाब घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान कर रहा है और वर्तमान में राज्य के 90 प्रतिशत घरों को शून्य बिल मिल रहा है।

संपादकीय

बढ़ता प्रदूषण

सदियों से, भारत में छह मौसमों (बसंत, गर्मी, मानसून, पतझड़, सर्दी और शीत ऋतु) का अपना एक क्रम रहा है। हर मौसम अपनी अलग खूबसूरती, मौसम और लाइफस्टाइल लेकर आता है। लेकिन आज बढ़ते प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की वजह से यह कुदरती क्रम बिगड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रदूषण का राक्षस धीरे-धीरे हमारे प्यारे मौसमों को निगल रहा है। मौसम बदलने के बिगड़ते रूप का मतलब है कि

अब, खासकर उत्तर भारत में, छह के बजाय सिर्फ़ तीन मुख्य मौसम ही महसूस होते हैं- सर्दी, गर्मी और मानसून। और वे भी अपने तय समय पर नहीं आते। पहले, अक्टूबर के आखिर में हल्की सर्दी (हेमंत) शुरू हो जाती थी, जो दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की सर्दी (शिशिर) में बदल जाती थी। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानसून बढ़ रहा है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून की बारिश जारी रहती है, और तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे सर्दियों के मौसम का अच्छा एहसास लगभग खत्म हो जाता है। ठंड का मौसम भी छोटा हो गया है। बसंत की हवा गायब होना- बसंत (मार्च-अप्रैल) को एक सुहावना मौसम माना जाता था। लेकिन, पिछले कुछ सालों से मार्च-अप्रैल से ही गर्मी की लहरें शुरू हो गई हैं। इस वजह से, बसंत की हवा अब महसूस नहीं होती, और हमें गर्मियों की गर्मी ही झेलनी पड़ती है। अनियमित बारिश- प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज ने मानसून के पैटर्न को बदल दिया है। ज़्यादा बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ आती है, जबकि कम बारिश से दूसरों में सूखा पड़ता है, जिससे खेती का कैलेंडर पूरी तरह से बिगड़ जाता है। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर इस बदलाव का मुख्य कारण इंसानों द्वारा किया गया प्रदूषण और उससे होने वाली ग्लोबल वार्मिंग है। एयर पॉल्यूशन (स्मॉग)- सर्दियों में शहरों को ढकने वाला ज़हरीला स्मॉग सूरज की रोशनी को धरती तक पहुँचने से रोकता है। यह रात के तापमान को कम करता है, लेकिन दिन में ठंडक के प्राकृतिक एहसास को रोकता है, जिससे सर्दियाँ अच्छी नहीं लगतीं। फॉसिल फ्यूल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ गया है। ये गैसें धरती के चारों ओर एक परत बना देती हैं, जो गर्मी को बाहर निकलने से रोकती हैं, जिससे दुनिया का औसत तापमान बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ तापमान मौसमों के समय और तेज़ी को बिगाड़ रहा है। ओज़ोन की कमी- हवा के प्रदूषण से स्ट्रेटोस्फीयर में ओज़ोन लेयर को भी नुकसान होता है, जिससे धरती पर जीवन के लिए खतरा बढ़ जाता है और मौसमी संतुलन बिगड़ जाता है। सेहत और खेती पर गंभीर असर। मौसम में इस गड़बड़ी का हमारी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है- सेहत का संकट- तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव, स्मॉग और प्रदूषित पानी से सांस की बीमारियां (अस्थमा), एलर्जी, दिल की बीमारियां और डेंगू और मलेरिया जैसी फैलने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। खेती का नुकसान- अनियमित बारिश और बढ़ते तापमान से फसल चक्र बिगड़ रहा है। चावल, गेहूं और कपास जैसी ज़रूरी फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे खाने की सुरक्षा को खतरा है। प्रदूषण, खासकर हवा में बढ़ते पार्टिकुलेट मैटर और ग्रीनहाउस गैसों से लगातार तापमान बढ़ रहा है। इसका मौसम चक्र पर सीधा असर पड़ा है। गर्मियां लंबी और गर्म हो गई हैं, जबकि सर्दियां छोटी और ज़्यादा अनियमित हो गई हैं। बारिश ज़्यादा बार होने लगी है, कभी कम, और कभी समय से पहले। अब, मौसम कैलेंडर के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रदूषण के लेवल के हिसाब से बदल रहा है। सर्दियों का कोहरा, जिसे कभी सुंदरता की निशानी माना जाता था, अब स्मॉग में बदल गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में स्मॉग की मोटी चादर ने सूरज की रोशनी को भी ढकना शुरू कर दिया है। इस वजह से, पतझड़ और सर्दियों की हल्की खुशबू फीकी पड़ने लगी है। लोगों को मौसम कम और प्रदूषण ज़्यादा पसंद आने लगा है। प्रदूषण के कारण तापमान में असामान्य बदलाव पौधों और जानवरों के जीवन चक्र पर असर डाल रहे हैं। फूल और फल अपने तय समय पर नहीं खिल रहे हैं। पक्षी अपने पारंपरिक प्रवास के रास्ते बदल रहे हैं। फसलों की बुवाई और कटाई का समय भी तेज़ी से अस्त-व्यस्त होता जा रहा है। यह असंतुलन भविष्य की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण की स्थिरता के लिए खतरा है।

आज तक आमने सामने
RNI NO -PUNHIN0/2013/54688
Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab
Editor Surinder Kumar (SK Saxena)
Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) के तथ्यों संबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

पारदर्शी भर्ती प्रणाली ने पंजाब के होनहार युवाओं के लिए खोले सुनहरी भविष्य के दरवाज़े-हरपाल सिंह चीमा

कहा, अब शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और अटूट लगन ही उज्ज्वल भविष्य के लिए पर्याप्त

मनदीप कौर

चंडीगढ़, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि पंजाब सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रणाली के माध्यम से सरकारी नौकरियों में केवल योग्यता और लगन को ही मापदंड बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि वास्तविक प्रतिभा को उसका हक और मान्यता मिले। उन्होंने ये विचार नव-नियुक्त हैपी कौर को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र भेंट करते हुए और वित्त विभाग में क्लर्क के रूप में आधिकारिक रूप से स्वागत करते हुए व्यक्त किए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हैपी कौर की उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी सफलता अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद की किरण और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि हैपी कौर के अब तक के जीवन की कहानी एक सशक्त उदाहरण है कि दृढ़ निश्चय और योग्यता के साथ कोई भी व्यक्ति चुनौतियों पर काबू पाकर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि हैपी कौर का सफर बेहद प्रेरणादायक है, जो पूरी तरह मेहनत और लगन पर आधारित है। वे ऐसे परिवार से आती हैं, जहां हर कदम केवल मजबूत इरादों के साथ ही आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके पिता लक्ष्मण सिंह परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पल्लेदार के रूप में कठोर मेहनत करते हैं, जबकि उनकी माता बलजीत कौर एक समर्पित घरेलू महिला हैं। परिवार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता उनके भाई में भी दिखाई देती है, जो

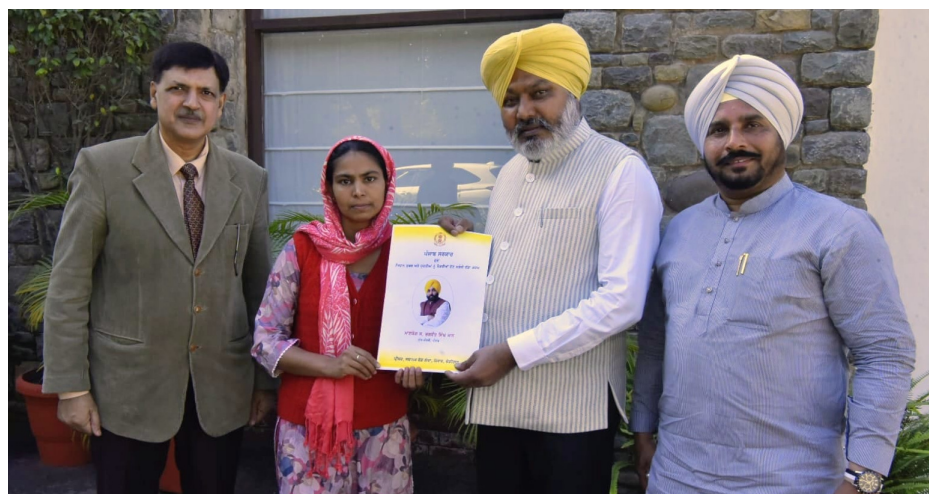

आर्ट्स ग्रेजुएट हैं और मनरेगा योजना के अंतर्गत अनुबंध पर ग्राम सेवक के रूप में अपनी सेवाएं देकर समाज में योगदान दे रहे हैं। साधारण पृष्ठभूमि और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हैपी कौर ने अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को दृढ़ता से पूरा किया और मास्टर ऑफ साइंस इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आई.टी.) की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पंजाब अधीन सेवा चयन बोर्ड (पी एस एस एस बी) की ओर से क्लर्क की पोस्ट के लिए आयोजित कठोर परीक्षा को पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक मुश्किलों के बावजूद सफलता प्राप्त करने का यह उदाहरण परिस्थितियों के विरुद्ध अथक प्रयासों की जीत का सशक्त प्रमाण है, जो समाज के हर वर्ग में राज्य की क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने ऐसा वातावरण तैयार किया है, जहां शिक्षा के प्रति समर्पण और अटूट लगन सचमुच उज्ज्वल भविष्य के द्वार खोल सकती है।

विधायक ज़िम्पा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत राशि के 1.56 करोड़ रुपए के स्वीकृति पत्र सौंपे

एस. के. सक्सैना

होशियारपुर, विधायक ब्रम शंकर ज़िम्पा ने वीरवार को पिछले समय भारी बरसात व बाढ़ से हुए मकान नुक़सान की भरपाई हेतु 104 प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ 56 लाख के स्वीकृति (सैंक्शन) पत्र वितरित किए। यह समारोह ज़िला प्रशासकीय काम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जहां लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से राहत सहायता के मंजूरी पत्र सौंपे गए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में जन-सेवा व प्रभावित परिवारों की मदद सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधायक ने बताया कि बाढ़ के दौरान जिन घरों को आंशिक या पूर्ण नुकसान पहुंचा, उनकी वित्तीय सहायता के लिए

पंजाब सरकार के राजस्व विभाग द्वारा विशेष गिरदावरी व क्षति आकलन रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र मंजूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत सहायता वितरण व पुनर्वास कार्यों को पारदर्शी व तेज़ी से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह राहत राशि प्रभावित परिवारों को सीधे बैंक खातों में के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या बिचौलियों की भूमिका न रहे। ब्रम शंकर ज़िम्पा ने राहत प्राप्त करने वालों के धैर्य व विश्वास की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान जनता का विश्वास ही हमारी ऊर्जा है और हम मिलकर क्षेत्र को पहले से अधिक मजबूत बनाएंगे। इस मौके पर मेयर सुरिंदर कुमार, प्रीतपाल, मंगी लाल, अमरजोत सैनी हलका संगठन इंचार्ज, कुलजीत सिंह, अमरजीत बाजवा, सरबजीत कौर सरपंच नंगल शहीदां भी मौजूद थे।

पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे-राज कमल चौधरी

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 209 के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.09.2025 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के सामान्य चुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवार 01.12.2025 (सोमवार) को सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 04.12.2025 (गुरुवार) होगी। नामांकन पत्रों की जांच 05.12.2025 (शुक्रवार) को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 06.12.2025 (शनिवार) शाम 03:00 बजे तक होगी। सभी नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित शपथ-पत्र तथा यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित राजनीतिक दल का आधिकारिक पत्र संलग्न होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मतदान 14.12.2025 (रविवार) को सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

इन चुनावों के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। पोल की गई वोटों की गिनती 17.12.2025 (बुधवार) को स्थापित गिनती केंद्रों पर की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव 23 जिला परिषदों के 357 जोनों तथा 154 पंचायत समितियों के 2863 जोनों के सदस्यों (प्रति जोन 1 सदस्य) के लिए कराया जाएगा। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,36,04,650 है, जिनमें 71,64,972 पुरुष, 64,39,497 महिलाएँ और 181 अन्य मतदाता शामिल हैं। इन चुनावों के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए कुल 19,181 बूथ स्थापित किए गए हैं। अन्य विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि आयोग ने जिला परिषद उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा 2,55,000/रुपए तथा पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए 1,10,000/रुपए निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि लगभग 96,000 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक जिले में चुनावों की सुव्यवस्थित निगरानी के लिए एक आईएएस/सीनियर पीसीएस अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। आयोग ने इन चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधीन आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के राजस्व क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। आचार संहिता की प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पंजाब सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) एक्ट, 2025 के माध्यम से व्यापक सुधार पेश किए-संजीव अरोड़ा

पंकज

चंडीगढ़, पंजाब में चल रही सोसाइटीज़ के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 'आप' के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में 1860 के पुराने सोसाइटीज़ एक्ट में संशोधन कर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) एक्ट, 2025 पेश किया है। कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि नया कानून विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज भलाई और चैरिटेबल गतिविधियों में शामिल सोसाइटीज़ के नियामक ढांचे को आधुनिक बनाता है। ये संशोधन सभी सोसाइटीज़ को समान, पारदर्शी शासन के अधीन लाकर सार्वजनिक फंड और कर-मुक्त स्रोतों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि पंजाब में सभी पंजीकृत सोसाइटीज़ अब सूचना का अधिकार (आर टी आई) एक्ट के तहत अनिवार्य रूप से कवर होंगी, जो पारदर्शिता

सुनिश्चित करते हुए लोगों के विश्वास को और मजबूत करेगा। सोसाइटीज़ द्वारा कानून की पालना सुनिश्चित करने और फंडों के दुरुपयोग या निर्धारित उद्देश्यों से भटकाव पर रोक लगाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रारों को सोसाइटीज़ से किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड मांगने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सोसाइटीज़ को अपनी सक्रियता बनाए रखने, सही और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने तथा अपने उद्देश्यों और प्रबंधन की समय-समय पर पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए हर पांच साल बाद अपनी रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत करनी होगी। पंजाब में सभी मौजूदा सोसाइटीज़ को संशोधित एक्ट लागू होने के एक वर्ष के भीतर इस एक्ट के तहत पुनः रजिस्टर करना होगा, जिससे उन्हें नए पालन और पारदर्शिता ढांचे के अधीन लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र में एक से अधिक सोसाइटीज़ को एक ही नाम के तहत रजिस्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जनता को भ्रमित कर सकता है। किसी भी सोसाइटी को रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति को बेचने, बदलने या निपटाने की अनुमति नहीं होगी, जो अनधिकृत लेन-देन पर रोक लगाने के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सोसाइटीज़ पंजीकृत हैं, वहां के डिप्टी कमिश्नरों (डी सीज) द्वारा सोसाइटीज़ की निगरानी की जाएगी। शिकायतें मिलने की स्थिति में डिप्टी कमिश्नर को तहसीलदार रैंक के अधिकारी के माध्यम से जांच संबंधी आदेश देने का अधिकार होगा। यदि खामियां पाई जाती हैं और निर्धारित समय में इन्हें ठीक नहीं किया जाता, तो एस.डी.एम. स्तर के प्रबंधक को नियुक्त किया जाएगा और सुव्यवस्थित कामकाज बहाल किया जाएगा। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि चुनी हुई प्रबंधक कमेटी भंग कर दी जाती है या प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है, तो समाजों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करते हुए छह महीने के भीतर नई चुनाव प्रक्रिया करवाई जानी चाहिए। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि सोसाइटीज़ के रूप में पंजीकरण कर कई चैरिटेबल संस्थाएं आय अर्जित कर लाभ प्राप्त करती हैं। यह एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक और चैरिटेबल संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी संस्थाएं लाभ प्राप्त करना जारी रखने हेतु संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, खेल संस्थाओं और अन्य लोक-हितैषी चैरिटेबल गतिविधियों में शामिल सोसाइटीज़ की निगरानी बढ़ाएंगे। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक ढांचे के दुरुपयोग को रोकना, लोकतांत्रिक और पारदर्शी कामकाज सुनिश्चित करना और सार्वजनिक संपत्तियों तथा चैरिटेबल स्रोतों की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) एक्ट, 2025 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर कामकाज सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि इस एक्ट का मसौदा उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव के. के. यादव की अगुवाई वाली टीम, निदेशक उद्योग सौरभि मलिक और पंजाब विकास आयोग की वाइस चेयरपर्सन सीमा बांसल द्वारा समयबद्ध ढंग से तैयार किया गया है।

मनदीप कौर, न्यूज़ एडीटर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

हरियाणा और पंजाब समाचार

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

16-30 November 2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, शहीद बाबू लाभ सिंह नगर में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने को लेकर सौंपा मांगपत्र

जालंधर में एक दर्जन से ज्यादा कालोनियों के प्रधानों ने पूर्व सांसद सुशील रिंकू से आरओबी या अंडरपास बनाने की रखी थी मांग

एस. के. सक्सैना

जालंधर, पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर जालंधर में मकसूदां रोड से शहीद बाबू लाभ सिंह नगर रोड के बीच पड़ती रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडरपास बनाने की मांग की है। इसे लेकर कुछ दिन पहले जालंधर की कई सोसाइटियों और मोहल्ला प्रधानों ने सुशील रिंकू को मांगपत्र सौंपा था। अब सुशील रिंकू ने रेलमंत्री से मिलकर आरओबी या अंडरपास बनाने की मांग रखी है।

पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने बताया कि कुछ दिन पहले शहीद बाबू लाभ सिंह नगर, अमर नगर, न्यू अमर नगर, आर्य नगर, कबीर नगर, शीतल नगर, राज नगर, राजा गार्डन, हरदेव नगर, न्यू सब्जी मंडी, फैंड्स कालोनी, ग्रेटर कैलाश समेत कई कालोनियों की सोसाइटियों के प्रधानों और अन्य पदाधिकारियों ने शहीब बाबू लाभ सिंह नगर के पास रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज या फिर रेलवे अंडरपास बनाने की मांग की थी।

शहर की सोसाइटियों और प्रधानों की मांग पर सुशील रिंकू ने दिल्ली में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने रेलमंत्री को बताया कि जालंधर में मकसूदां रोड से शहीद बाबू लाभ सिंह नगर के बीच रेलवे क्रासिंग पर हमेशा भारी भीड़ रहती है। लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर यहां रेलवे ब्रिज या अंडर पास बन जाए तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी।

सुशील रिंकू ने बताया कि रेलमंत्री ने मांगपत्र स्वीकार करते हुए रेलवे अफसरों को इस पर रिपोर्ट मांगी है। रेल मंत्री ने अश्वासन दिया है कि शहर की सोसाइटियों की मांगों पर जरूर काम होगा। उन्होंने कहा कि आरओबी ये रेलवे अंडरपास के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसकी जरूरत है, उसे अवश्य बनाया जाएगा।

विश्वविद्यालय के उत्थान में शिक्षक व कर्मचारियों की अहम भूमिका: प्रो. सोमनाथ सचदेवा

कुवि के सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से विदाई पार्टी

मनदीप कौर

कुरुक्षेत्र, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक 28 नवम्बर - कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 शिक्षकों व दो गैर–शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवसर पर प्रशासन की ओर से विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विश्वविद्यालय के उत्थान में शिक्षकों व कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक व कर्मचारी शिक्षण संस्थान का मजबूत आधार होते हैं जो संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों व कर्मचारियों से औपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों के लिए सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा तथा भविष्य में भी सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारियों के अनुभव विश्वविद्यालय के काम आएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी के सुझाव लिए व उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

कुवि कुलसचिव लेफ्टिनेंट डॉ. वीरेन्द्र पाल ने भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों ने अपने विचार व अनुभव साझा किए। सभी ने भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय के लिए हर समय तैयार रहने का आश्वासन दिया व इस विदाई पार्टी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार प्रकट किया। सेवानिवृत्त होने वालों में कामर्स विभाग की प्रोफेसर नीलम रानी, इंस्ट्यिूट ऑफ इंटिग्रेटिड एंड आनर्स स्टडीज़ के प्रोफेसर अमृत सिंह, प्रोफेसर संतोष दहिया व एसोसिएट प्रोफेसर नवोदिता, बायो–कैमिस्ट्री विभाग से स्टोर कीपर महिपाल तथा संचालन शाखा से माली नाथू राम शामिल हैं।

इस अवसर पर कुलसचिव लेफ्टिनेंट डॉ. वीरेन्द्र पाल, प्रो. महावीर नरवाल, प्रो. अश्विनी कुश, लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया, डॉ. जितेन्द्र जांगड़ा, कुंटिया महासचिव रविंद्र तोमर, अजमेर सिंह, सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारजन मौजूद थे।

पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए सरकार तैयार-मान

अगले वर्ष के अंत तक 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य संपूर्ण करने बाबत बताया

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 16,209 करोड़ रुपये की कुल लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के साथ पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अगले वर्ष के अंत तक पंजाब के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन सड़कों के निर्माण में विश्व–स्तरीय मानकों और सुरक्षा नियमों का पालन हो, और इसके लिए निर्माण के साथ पाँच वर्षों की रख–रखाव की अनिवार्य शर्त भी जोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कदम से राज्य में

परिवहन सुचारू होगा और ग्रामीण अवसंरचना को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही 4,092 करोड़ रुपये की लागत से 19,373 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण करा चुकी है। इस वर्ष बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में सड़कों को भारी नुकसान हुआ था, परन्तु सरकार ने कठिन परिश्रम से इस परियोजना को पूरा किया और ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में भी पाँच वर्ष की रख–रखाव शर्त जोड़ी गई है, जो एक मिसाल है। इसके साथ–साथ सड़कों पर उचित दिशा–सूचक तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ भी सुनिश्चित की जाएँगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ओर से यह मांग थी कि सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता मानकों को बरकरार रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पंजाब के लोगों की बेहतर सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के तहत पंजाब सरकार ने पीएमबी, पीडब्ल्यूडी, शहरी स्थानीय निकायों सहित कई एजेंसियों और जनप्रतिनिधियों को इस राज्यव्यापी अभियान से जोड़ा है। राज्य सरकार ने पंजाब की सभी सड़कों का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर उनकी मरम्मत और उन्नयन की जरूरी सूची तैयार की है। अब लक्ष्य है कि अगले वर्ष के अंत तक 16,209 करोड़ की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वॉड सड़कों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी कर रहा है और घटिया सामग्री उपयोग की शिकायतें मिलने पर कई ठेकेदारों के अनुबंध रद्द भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कोई भी ठेकेदार या कर्मचारी घटिया काम में लिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अभी तक केंद्र से आर डी एफ का एक भी रुपया नहीं मिला है और पंजाब सरकार यह पूरा निर्माण अपने संसाधनों से कर रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने 1,600 करोड़ के विशेष पैकेज में से एक भी रुपया पंजाब को नहीं दिया और पंजाब भाजपा नेतृत्व इस बारे में झूठ फैला रहा है। जो भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि फंड जारी किए गए हैं, उन्हें समझना चाहिए कि यह केंद्र की नियमित योजनाओं के फंड हैं, जो पंजाब को वैसे भी मिलते–चाहे बाढ़ आई होती या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बिना कारण श्रेय ले रहे हैं, जबकि कोई विशेष पैकेज जारी नहीं हुआ है।

पीआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अपील की कि सभी कर्मचारी काम पर लौटें और सरकार से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों को हल करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है और कुछ मामले अदालतों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जनता की सुविधा को देखते हुए आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार पीआरटीसी कर्मचारियों की समस्याओं को समझती है और उनके समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब सरकार जल्द ही 900 नई सरकारी बसें अपने बेड़े में शामिल करेगी, जिससे जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएँ मिलेंगी। राज्य की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को अपनी गतिविधियाँ तुरंत बंद कर देनी चाहिए और उन्हें पंजाब के सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई गैंगस्टर किसी नागरिक को नुकसान पहुँचाता है या कोई अपराध करता है, तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि उसे कड़े सबक सिखाए जाएँगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है और उनके नापाक इरादों को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने राज्य में शांति, सद्भाव और भाईचारे को कायम रखने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा दिवंगत खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिवार से मिलने को राजनीति कहे जाने पर भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे खेल प्रेमी हैं और परिवार के दुख में सहभागी होने के लिए गए थे। किसी खिलाड़ी के परिवार से मिलना राजनीति नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है, क्योंकि हरियाणा में खेल अवसंरचना बेहद खराब स्थिति में पहुँच चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खराब खेल सुविधाओं के कारण राज्य के दो होनहार खिलाड़ियों ने हाल ही में अपनी जानें गंवाई हैं। जब भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहा है, तब हरियाणा में कमजोर खेल ढाँचा खिलाड़ियों की जान ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुराली बस अड्डे के सुबह के दौरे के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जनता को हो रही समस्याओं का प्रत्यक्ष जायज़ा लेने गए थे। उन्होंने बताया कि रूपनगर के डिप्टी कमिश्नर को स्थानीय और लंबी दूरी की बस सेवाओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि यह दौरा कमियाँ खोजने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा के लिए किया गया था।

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षक संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी–7 ऊर्जा रिव्यू के विशेषज्ञ रेफरेंस ग्रुप में शामिल

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

बठिंडा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगल पहचान बनाते हुए पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू पंजाब) ने एक और उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की है। विश्वविद्यालय के दो प्रतिष्ठित प्रोफेसरों / शिक्षाविदों – कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी और प्रो. फेलिक्स बास्ट (विभागः वनस्पति विज्ञान) को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया–प्रशांत – यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (यूएन ईएससीएपी) द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल–7 (एसडीजी–7ः सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा) के 2026 गोल प्रोफाइल रिव्यू के विशेषज्ञ रेफरेंस ग्रुप में शामिल किया गया है। दोनों प्रोफेसरों को वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही तैयारी रिपोर्ट के लिए वैज्ञानिक और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया तथा ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा दक्षता पर रणनीतिक इनपुट दिए। एसडीजी–7 का उद्देश्य सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के व्यापक उपयोग एवं ऊर्जा दक्षता में सुधार को बढ़ावा देना है। प्रख्यात भूवैज्ञानिक, ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद एवं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी तथा समुद्री जीवविज्ञानी एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के एशिया–प्रशांत क्षेत्र के सलाहकार प्रो. फेलिक्स बास्ट की यूएन–ईएससीएपी में भागीदारी विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल रीजनल फोकल पॉइंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने दोनों विशेषज्ञों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना की। एसडीजी–7 के इस अंतरराष्ट्रीय रेफरेंस ग्रुप में दुनिया के प्रमुख संस्थान – ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, आरएमआईटी यूनिवर्सिटी, और कर्टिन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं। इस ग्रुप में

सीयू पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रो. तिवारी और प्रो. बास्ट ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराई। प्रो. फेलिक्स बास्ट की उपलब्धियों में भारत के अंटार्कटिक मिशन में अभियान वैज्ञानिक के रूप में योगदान, राष्ट्रपति द्वारा इंस्पायर्ड टीचर अवॉर्ड तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा टीचिंग इनोवेटर अवॉर्ड प्राप्त करना शामिल है। कुलपति प्रो. राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में सीयू पंजाब ने वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन – वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 600–800 बैंड में स्थान प्राप्त किया है, जो विश्वविद्यालय के मजबूत अनुसंधान निष्पादन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। प्रो. तिवारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के ड्राफ्ट निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं और वह पर्यावरणीय स्थिरता तथा प्रकृति–अनुकूल जीवनशैली के प्रबल समर्थक रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण वैश्विक योगदान पर विचार व्यक्त करते हुए कुलपति प्रो. राघवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने कहा- ‘एसडीजी–7 जैसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक लक्ष्य पर रणनीतिक मार्गदर्शन देना पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। यह सहभागिता आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत भविष्य सुनिश्चित करने हेतु वैज्ञानिक समाधानों को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग में हमारी निरंतर प्रगति यह दर्शाती है कि सीयू पंजाब स्वच्छ ऊर्जा पहुंच और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में बौद्धिक नेतृत्व निभाने के लिए संकल्पित है।’ भारत की वैश्विक भूमिका पर टिप्पणी करते हुए प्रो. फेलिक्स बास्ट ने कहा- ‘हमारे रिव्यू से स्पष्ट होता है कि वैश्विक ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवर्तनकारी नीतियों की आवश्यकता है। भारत, पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली – लाइफ़स्टाइल फॉर इन्वायरनमेंट और राष्ट्रीय सौर मिशन / नेशनल सोलर मिशन जैसे बड़े रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से एक मिसाल स्थापित कर रहा है। व्यवहार–परिवर्तन और प्रणालीगत निवेश का यह संतुलन एशिया–प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी–7 की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो रहा है।’ यूएन ईएससीएपी गोल प्रोफाइल रिव्यू के अंतिम सबमिशन के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच – हाई–लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचएलपीएफ) की तैयारियों को गति मिल गई है। सीयू पंजाब अनुसंधान–आधारित नीति–निर्माण, वैश्विक जलवायु कार्रवाई और सतत नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे विश्वविद्यालय की पहचान वैज्ञानिक उत्कृष्टता, हरित विकास और जिम्मेदार नागरिकता के केंद्र के रूप में और सुदृढ़ होगी।

आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी तय करे सरकार - खन्ना

फगवाड़ा में आवारा कुत्तों की समस्या का मामला

मनदीप कौर

होशियारपुर, पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पंजाब में लगातारआवारा कुत्तों की बढ़ रही संख्या का कारण पंजाब सरकार और पशुपालन विभाग की अनदेखी है। खन्ना ने इस मुद्दे पर फगवाड़ा में आवारा कुत्तों की बढ़ रही संख्या के चलते निवासियों को पेश आ रही समस्या के विषय पर प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए इस मामले को प्रदेश मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाया है। खन्ना ने कहा कि पशुपालन विभाग की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि आवारा

कुत्तों की बढ़ रही संख्या को रोकने के लिए कुत्तों की नसबंदी और उनकी वैक्सीनेशन जैसे मानवीय कदम उठाते हुए इनकी संख्या को कंट्रोल करने के प्रयास करे परन्तु सरकार और विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं है। खन्ना ने आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि पंजाब सरकार को यह निर्देश दिए जाएं कि फगवाड़ा के साथ साथ पूरे पंजाब में आवारा कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी तय की जाये ताकि फगवाड़ा सहित पुरे पंजाब में इस समस्या का हल हो सके।

आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी ने कोलंबो में श्रीलंका नौसेना द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 में भाग लिया

पंकज

नई दिल्ली–भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत स्वदेशी रुप से निर्मित फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी के साथ, 27 से 29 नवंबर 2025 तक कोलंबो में श्रीलंका नौसेना द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्?व कर रहा है। यह आयोजन श्रीलंका नौसेना की 75वीं वर्षगांठ समारोह का एक हिस्सा है और इसमें कई देशों के नौसेनिक जहाजों, प्रतिनिधिमंडलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी शामिल है। यह यात्रा दोनों जहाजों की पहली विदेश तैनाती को दर्शाती है और क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। स्?वदेशी रूप से निर्मित और राष्?ट्र के गौरव आईएनएस विक्रांत की अंतर्राष्?ट्रीय फ्लीट रिव्?यू में पहली भागीदारी

हिन्?द महासागर क्षेत्र में भागीदार नौसेनाओं के साथ भारत के निरंतर जुड़ाव को उजागर करती है तथा सहयोग और अंतर संचालनीयता के माध?यम से शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भारत के ज़ोर देने को दर्शाती है। हाल ही में कमीशन किए गए आईएनएस उदयगिरी की भागीदारी भारत की उन्?नत स्?वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं तथा आईओआर में इसकी संतुलित, विस्?तृत नौ?सैनिक उपस्थिति को और प्रदर्शित करती है। कोलंबो में अपने ठहराव के दौरान ये जहाज प्रमुख प्रमुख आईएफआर कार्यक्रमों भाग लेंगे, जिनमें औपचारिक फ्लीट रिव्यू, सिटी पेरड, सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां और पेशेवर नौसैनिक संवादों शामिल हैं। जनसंपर्क पहलों के हिस्?से के रूप में ये जहाज आईएफआर 2025 के दौरान आगंतुकों के लिए भी खुले रहेंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शुक्रवार को गुलाबगंज में पदयात्रा, महिला सम्मान समारोह और सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए

उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम करेंगे ताकि जनता को योजनाओं का लाभ मिले

एस. के. सक्सैना

नई दिल्ली–केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के गुलाबगंज पहुंचें। केन्द्रीय मंत्री, यहां दांगी समाज के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को समर्पित पदयात्रा, जन–समस्या निवारण शिविर, महिला सम्मान समारोह, हितग्राही सम्मेलन और सांसद खेल महोत्सव के तहत कबड्डी के फाइनल में शामिल हुए। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकान का गृह प्रवेश भी किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं, हमारे सभी नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं कि, उन्होंने उत्साह से आज पदयात्रा का आयोजन किया। जिन्होंने हमारा देश बनाया उनको प्रणाम करना परम कर्तव्य है। इस अवसर पर जनता के कल्याण के लिए आज शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सेंकड़ों भाई–बहन चाहे वो

किसान हो, बहनें हो, कारीगर हो, बेटा–बेटी हो अलग–अलग योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने का काम किया गया है। जनता की जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है और इसलिए अब तय किया है कि उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम करेंगे, जिसमें लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जन–सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता केन्द्रीय कृषि मंत्री ने शुक्रवार को गुलाबगंज में आयोजित जन–समस्या निवारण शिविर में आमजन से सीधा संवाद किया। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। शिविर में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना समेत केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कई किसानों ने फसल बीमा के क्लेम में देरी और तकनीकी खामियों की शिकायत की, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने किस्त जारी ना होने जैसी समस्याएं बताई। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, सरकार की योजनाओं का लाभ शत–प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल बीमा संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके। शिवराज सिंह ने कहा कि, जन–सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे शिविर समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम बन रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद-2025 के तीसरे संस्करण में शामिल हुईं

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारी आतंकवाद–रोधी और निवारक रणनीति में एक निर्णायक क्षण है–राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

रमन कुमार

नई दिल्ली–राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (27 नवंबर, 2025) नई दिल्ली में भारतीय सेना के सेमिनार – चाणक्य रक्षा संवाद – 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने देश की संप्रभुता की रक्षा करने में अपने सैन्?य अनुभव और देशभक्ति का उदाहरण पेश किया है। हर सुरक्षा चुनौती के दौरान, चाहे वह पारंपरिक हो, आतंकवाद का मुकाबला हो या मानवीय, हमारे सशस्?त्र बलों ने उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता और संकल्प का प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर की हालिया सफलता हमारी आतंकवाद–रोधी और निवारक रणनीति का निर्णायक क्षण है। दुनिया ने न केवल भारत की सैन्य क्षमता को देखा, बल्कि शांति की खोज में दृढ़ता से, लेकिन जिम्मेदारी से कार्य करने की देश की नैतिकता पर भी ध्यान दिया। अपनी परिचालन भूमिका से परे, भारतीय सशस्?त्र बल राष्ट्रीय विकास के स्तंभ बने हुए हैं। हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के अलावा, उन्होंने बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, पर्यटन और शिक्षा के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में भी मदद की है। राष्ट्रपति ने कहा कि

आज का भू–राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। प्रतिस्?पर्धी शक्ति केंद्रों, तकनीकी व्यवधानों और गठबंधनों को बदलकर अंतर्राष्ट्रीय व?यवस्?था को फिर से गढ़ा जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के नए क्षेत्र–साइबर, अंतरिक्ष, सूचना और ज्ञानात्मक युद्ध शांति और संघर्ष के बीच की लकीरों को मिटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के सभ्यतागत लोकाचार से प्रेरित होकर, हमने दिखाया है कि रणनीतिक स्वायत्तता वैश्विक उत्?तरदायित्?व के साथ सह–अस्तित्व में हो सकती है। हमारी कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सशस्त्र बल मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं, जो शांति चाहता है, लेकिन पूरी ताकत और दृढ़ विश्?वास के साथ अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की रक्षा करने को तैयार है। राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्?नता हुई कि सेना परिवर्तन के दशक के दौरान मात्रात्मक परिणामों के माध्यम से खुद को बदल रही है। यह संरचनाओं में सुधार कर रही है, सिद्धांतों को पुनर्निर्देशित कर रही है और सभी क्षेत्रों में भविष्?य के लिए तैयार और मिशन–सक्षम होने के लिए अपनी क्षमताओं को पुनर्परिभाषित कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन रक्षा सुधारों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना युवाओं और मानव संसाधन में निवेश कर रही है। वह शिक्षा, एनसीसी विस्तार और खेल के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति का संचार कर रही है। उन्होंने उल्?लेख किया कि भूमिका और चरित्र दोनों में, युवा महिला अधिकारियों और सैनिकों के योगदान का विस्तार सेना में समावेश की भावना को बढ़ावा देगा। इससे और भी युवा महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल होने और अन्य पेशे अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि चाणक्य रक्षा संवाद–2025 की चर्चा और परिणाम हमारी राष्ट्रीय नीति की भविष्य की रूपरेखा को आकार देने के लिए नीति निर्माताओं को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास व?यक?त किया कि हमारे सशस्त्र बल उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।

रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति का चिनाब व अंजी रेल पुलों का अध्ययन दौरा

रमेश कुमार

आज दिनांक 26 नवंबर 2025, को उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में स्थित नव निर्मित चिनाब और अंजी खड्ड रेल पुलों का क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति (ऋष्ट) के सदस्यों द्वारा अध्ययन दौरा किया गया। इस अध्ययन दौरे का मुख्य उद्देश्य रेलवे अवसंरचना के निमार्ण में तकनीकी नवाचार और भारतीय रेलवे के विकास को देखना तथा इन पुलों के निमार्ण की जटिलताओं को समझने पर केन्द्रित था । इस अध्ययन दौरे के दौरान 'ऋष्ट सदस्यों के साथ उत्तर रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक (सामान्य) मंडल रेल प्रबंधक, श्री विवेक कुमार व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री उचित सिंघल व मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अगर चिनाब और अंजी खड्ड रेल पुल की विशेषताओं की बात करें, तो यह दोनों पुल उधमपुर – श्रीनगर

– बारामूला रेल लिंक परियोजना (स्क्क्रञ्ज) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अदभुत नमूना हैं। इन पुलों की खुबी को देखे, तो सबसे पहले चिनाब पुल, यह पुल चिनाब नदी पर बनाया गया हैं, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर से अधिक हैं। इस पुल को सुरक्षा के लिहाज से देखें, तो 8 तीव्रता के भुकंप के झटके और 266 कि भी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का सामना करने में भी सक्षम हैं। दुसरे क्रम में अंजी खड्ड रेल पुल की बात करें, तो यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल हैं। जो चुनौतीपूर्ण भूभाग पर बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 331 मीटर हैं। जो एक बहेतर कनेक्टीविटी को सुनिश्चित करता हैं। यह अध्ययन दौरा 'ऋष्ट के सदस्यों को इन महत्वकांक्षी परियोजना को करीब से देखने और रेलवे के सामने आने वाली तकनीकी और परिचालन चुनोतियों को समक्षने का अवसर प्रदान करेगा। यह अध्ययन दौरा रेलवे के बुनियादी ढांचे को को बेहतर बनाने और रेलवे उपयोगकर्ताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस दौरे से प्राप्त जानकारी का उपयोग भविष्य की परियोजनाओं को और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से योजना बनाने में किया जाएगा।

जमाना खराब है, समाज सेवको जरा बच के – एडवोकेट भारती

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा
ब्यूरो चीफ पंजाब एवं हरियाणा

गत दिवस मोगा के समाज सेवी व शहर के मेयर बलजीत सिंह चानी को आम आदमी पार्टी ने घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुऐ उनसे मेयर का पद भी वापिस ले लिया है। उनके ऊपर एक अफीम तस्कर की मदद करने के आरोप की चर्चा के चलते यह घटनाक्रम हुआ है। हालांकि बलजीत सिंह चानी मेयर के साथ–साथ एक समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। कुछ माह पहले भी शहर के कुछ अन्य समाजसेवी भी कुछ गलत कार्यों के लिए चर्चा में आ चुके हैं।कुछ को तो अदालतों में जमानत के लिए भी जाना पड़ा। इससे पहले भी शहर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी समाज सेवा के कार्यों को लेकर बदनाम हो चुके हैं। लगता है शहर के समाजसेवियों की ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं चल रही है। यह कहना है एडवोकेट प्रदीप भारती। उन्होंने शहर के समाजसेवियों से अनुरोध किया

है कि अब समाज सेवा का चेहरा लगाने से पहले, जरा अपने आप को और आसपास के वातावरण को अच्छी तरह से पहचान ले, क्योकि जमाना खराब है,और यदि सच में किसी को समाज सेवा करने का शौक है तो अपने आप को राजनीतिक नेताओं से लोगों से दूर रखें, अन्यथा समाज सेवा पर आरोप प्रत्यारोप लगना निश्चित है।दूसरी तरफ भारती का कहना है कि कुछ समाज सेवको पर इस तरह के आरोप लगने से इस बात से भी इंकार नही किया जा सकता कि क्या सच में कहीं इन की दाल काली तो नहीं है ?

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री बिट्टू ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली का किया दौरा

भारत सरकार एससीएल मोहाली में 4,500 करोड़ का निवेश करेगी; प्राइवेटाइजेशन से इंकार

मनदीप कौर

मोहाली–केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल), मोहाली का दौरा किया और कार्य प्रगति व चल रही आधुनिकीकरण गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार एससीएल मोहाली को अपग्रेड और विस्तार देने के लिए ?4,500 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि शामिल होगी, जिसका लक्ष्य मौजूदा स्तर की तुलना में वेफर उत्पादन को 100 गुना तक बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया, इसमें कोई शक नहीं है। एससीएल मोहाली का पूर्ण आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसे प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाएगा। आगे एक बड़ा सफ़र है, और भारत इसके लिए तैयार है। कार्यक्रम के दौरान, एससीएल मोहाली में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को 17 अकादमिक संस्थानों के स्टूडेंट्स द्वारा डिज़ाइन किए गए 28 चिप्स सौंपे गए। ये चिप्स इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (ईडीए) टूल्स का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जो छात्रों को चिप्स–टू–स्टार्टअप (सी2एस) प्रोग्राम के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एससीएल में अब तक स्टूडेंट्स द्वारा डिज़ाइन किए गए कुल 56 चिप्स बनाए जा चुके हैं। मंत्री ने सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और अभ्युदय ट्रेनिंग ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी में पुरानी पीढ़ी के फैब्रिकेशन टूल्स से सुसज्जित एक क्लीनरूम लैब प्रदर्शित की गई है, जो छात्रों को सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी सुविधा का वास्तविक अनुभव कराती है। अभ्युत्थान प्रशिक्षण ब्लॉक में सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग से संबंधित ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल शामिल हैं,

साथ ही फायर और सेफ्टी की हैंड्स–ऑन ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एससीएल मोहाली के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है और प्रमुख विज़न क्षेत्रों को रेखांकित किया है। एससीएल को आधुनिक तकनीक के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा और सरकार 4,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसमें उत्पादन क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी शामिल होगी, जिसका लक्ष्य मौजूदा स्तर से वेफर उत्पादन को 100 गुना तक बढ़ाना है। एससीएल मोहाली छात्रों, शोधकर्ताओं और स्टार्ट–अप्स को फैब्रिकेशन सुविधा उपलब्ध कराकर उनका समर्थन जारी रखेगी, जिससे वे अपने चिप डिज़ाइन को वास्तविक सिलिकॉन में बदल सकें। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जहाँ लगभग 300 विश्वविद्यालयों के छात्र सरकारी सहायता से प्राप्त वर्ल्ड–क्लास ईडीए टूल्स का उपयोग करके सेमीकंडक्टर चिप्स डिज़ाइन कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह इकोसिस्टम दुनिया में एक अनूठा मॉडल है। उन्होंने दोहराया कि एससीएल टैलेंट डेवलपमेंट, इनोवेशन और स्टार्ट–अप्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म बना रहेगा। एससीएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही फैब्रिकेशन सुविधा भविष्य में और बढ़ाई जाएगी। एससीएल के अगले चरण के मॉडर्नाइज़ेशन कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए भारत सरकार ने पंजाब सरकार से 25 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध भी किया है।

मंत्री ने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है, और भारत स्वदेशी चिप विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेगा। सी–डैक, डीआरडीओ और अन्य संस्थानों का एक मज़बूत समूह मिलकर घरेलू चिप्स के डिज़ाइन, उत्पाद विकास और विनिर्माण पर काम करेगा।

ज़मीन-जायदाद की 'ईज़ी रजिस्ट्री' व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य-मुख्यमंत्री

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय

एस. के. सक्सैना

फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज एक और क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए ज़मीन–जायदाद की 'ईज़ी रजिस्ट्री' (आसान व्यवस्था) को लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के मकसद से इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत के गवाह बने सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दशकों से ज़मीन–जायदाद की रजिस्ट्रेशन को जटिल और समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया माना जाता रहा है। इसके लिए बार–बार सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत परेशानी होती थी और देरी व भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए संबंधित सब–रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे अतिरिक्त बोझ और असुविधा होती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 卐आसान रजिस्ट्री卐 व्यवस्था लागू हो जाने से पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन सरल, तेज़ और पारदर्शिता के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 卐ईज़ी रजिस्ट्री卐 प्रणाली नागरिकों के लिए अनावश्यक देरी और परेशानी को पूरी तरह खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार किसी राज्य ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन को इतना सरल बनाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल के तहत अब एक जिले के अंदर कोई भी सब–रजिस्ट्रार कार्यालय उस जिले के किसी भी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों को रजिस्टर कर सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक मात्र 500 रुपए की नाममात्र फीस देकर 'सेल डीड' ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से तैयार करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 卐सरकार तुहाडे दुआर卐 योजना के तहत लोग इस सेवा का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ केवल 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब तहसीलदार ज़मीन–जायदाद की रजिस्ट्रेशन पर अनावश्यक आपत्ति नहीं लगा सकेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके लिए 48 घंटे की समय–सीमा तय की गई है और यदि कोई आपत्ति लगाई जाती है तो उसे तुरंत संबंधित डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाएगा, जो यह पुष्टि करेंगे कि आपत्ति वैध है या नहीं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के हर चरण की अपडेट मिलती रहेगी और यदि कोई रिश्वत मांगता है तो व्हाट्सएप पर ही शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अब डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि हर संपत्ति की रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से पूरी हो। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से मोहाली के सब–रजिस्ट्रार कार्यालय को हेल्प डेस्क और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र के साथ अपग्रेड किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन केवल उसी सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में हो सकती थी जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित थी। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रगति या उठाई गई किसी भी आपत्ति की जानकारी तक नहीं मिलती थी। अब दस्तावेज़ जमा करने से लेकर मंजूरी, भुगतान, आपत्ति और अंतिम दस्तावेज़ तैयार होने तक हर चरण की पल–पल की जानकारी व्हाट्सएप पर मिलेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आपत्ति उठाने या दस्तावेज़ सत्यापन के लिए 48 घंटे की समय–सीमा तय की गई है और यह व्यवस्था सेल डीड रजिस्टर करने से जुड़े अतिरिक्त खर्चों को भी कम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 卐ड्राफ्ट माई डीड卐 सुविधा के जरिए कोई भी व्यक्ति सेवा केंद्र या सेवा सहायक की मदद से अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ खुद लिख सकेगा। उन्होंने कहा कि अलग से लेन–देन के सबूत पेश करने की जरूरत नहीं होगी, इससे नागरिकों को बार–बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को अब अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ इकट्ठा करने के लिए बार–बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद नागरिकों को व्हाट्सएप पर ही पुष्टि की सूचना मिल जाएगी, जिससे वे एक ही विज़िट में अपना सेल डीड ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार और नागरिक–हितैषी सुधार लाने और सेवा केंद्रों व हेल्पलाइन नंबर 1076 को और सक्षम बनाने पर काम कर रही है ताकि नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक दफ्तरों में न जाना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों में यह ऐतिहासिक मील का पत्थर लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है ताकि लोग सेवाएं सुचारू और परेशानी–मुक्त ढंग से प्राप्त कर सकें।

पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, शहीद बाबू लाभ सिंह नगर में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने को लेकर सौंपा मांगपत्र

जालंधर में एक दर्जन से ज्यादा कालोनियों के प्रधानों ने पूर्व सांसद सुशील रिंकू से आरओबी या अंडरपास बनाने की रखी थी मांग

मनदीप कौर

जालंधर, 2025। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर जालंधर में मकसूदां रोड से शहीद बाबू लाभ सिंह नगर रोड के बीच पड़ती रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज या रेलवे अंडरपास बनाने की मांग की है। इसे लेकर कुछ दिन पहले जालंधर की कई सोसाइटियों और मोहल्ला प्रधानों ने सुशील रिंकू को मांगपत्र सौंपा था। अब सुशील रिंकू ने रेलमंत्री से मिलकर आरओबी या अंडरपास बनाने की मांग रखी है। पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने बताया कि कुछ दिन पहले शहीद बाबू लाभ सिंह नगर, अमर नगर, न्यू अमर नगर, आर्य नगर, कबीर नगर, शीतल नगर, राज नगर, राजा गार्डन, हरदेव नगर, न्यू सब्जी मंडी, फैंड्स कालोनी, ग्रेटर कैलाश समेत कई कालोनियों की सोसाइटियों के प्रधानों और अन्य पदाधिकारियों ने शहीब बाबू लाभ सिंह नगर के पास रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज या फिर रेलवे अंडरपास बनाने की मांग की थी। शहर की सोसाइटियों और प्रधानों की मांग पर सुशील रिंकू ने दिल्ली में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने रेलमंत्री को बताया कि जालंधर में मकसूदां रोड से शहीद बाबू लाभ सिंह नगर के बीच रेलवे क्रासिंग पर हमेशा भारी भीड़ रहती है। लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर यहां रेलवे ब्रिज या अंडर पास बन जाए तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। सुशील रिंकू ने बताया कि रेलमंत्री ने मांगपत्र स्वीकार करते हुए रेलवे अफसरों को इस पर रिपोर्ट मांगी है। रेल मंत्री ने अश्वासन दिया है कि शहर की सोसाइटियों की मांगों पर जरूर काम होगा। उन्होंने कहा कि आरओबी ये रेलवे अंडरपास के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसकी जरूरत है, उसे अवश्य बनाया जाएगा।

जेई और ठेकेदार 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू

पंकज

चंडीगढ़, पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत विजीलेंस ब्यूरो ने आज दसूहा जिला होशियारपुर में पीएसपीसीएल के जूनियर इंजीनियर निर्मल सिंह और सरकारी मंज़ूरशुदा ठेकेदार सतनाम सिंह को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता के अनुसार शिकायतकर्ता–जो तहसील दसूहा का निवासी और टैक्सी चालक है–के पास गांव में 13 मरले का प्लॉट है, जिसमें से तीन–फ़ेज़ तारें पड़ोस के कांता पुत्र देसा सिंह की मोटर तक जाती थीं। शिकायतकर्ता ने पीएसपीसीएल सब–डिवीजन दसूहा में आवेदन देकर इन तारों को प्लॉट के एक ओर तब्दील करवाने की मांग की थी। उन्होंने आगे बताया कि जेई निर्मल सिंह ने साइट सर्वे किया और शिकायतकर्ता से अनुमान तैयार करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की। इसके बाद उसने रिश्वत के 5,000 रुपये और मांग लिए। बाद में जेई निर्मल सिंह और ठेकेदार सतनाम सिंह दोबारा शिकायतकर्ता के घर पहुंचे, जहाँ ठेकेदार ने तारें बदलने के लिए 12,000 रुपये की मांग की। बातचीत के बाद शिकायतकर्ता 10,000 रुपये देने पर तैयार हो गया, जबकि जेई ने पहले मांगे गए बचे 5,000 रुपये भी देने के लिए कहा। हालाँकि ठेकेदार ने मंजूरशुदा नक्शे के अनुसार तारें बदल दी थीं, लेकिन शिकायतकर्ता ने उसी दिन रिश्वत नहीं दी। इसके बाद दोनों आरोपी बार–बार फोन करके रिश्वत की मांग करते रहे। शिकायतकर्ता ने पूरी बातचीत अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और साक्ष्य के साथ विजीलेंस ब्यूरो से संपर्क किया।

जांच के बाद विजीलेंस ब्यूरो यूनिट जालंधर ने योजना बनाकर दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजीलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा तथा आगे की जांच जारी है।

एक राष्ट्रीय संकल्प-संपूर्ण सरकार और समाज साझा रूप से बाल विवाह मुक्त भारत की ओर अग्रसर

लेखिका
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी,
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार

एक ऐसे देश में जहाँ महिलाएँ और बच्चे एक अरब से ज़्यादा जीवनों का आधार हैं, उनका सशक्तिकरण महज़ एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह भारत की नियति का मार्ग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी शासन में, भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, जो वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को मानव–केंद्रित प्रगति के साथ जोड़ रहा है। नए भारत की कहानी केवल आर्थिक उपलब्धियों और बढ़ते वैश्विक कद में ही नहीं, बल्कि उन कक्षाओं में भी आकार ले रही है, जहाँ युवा मन विकसित होते हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जहाँ हमारे बच्चों का पालन–पोषण होता है, और उन घरों में जहाँ आकांक्षाएँ पनपती हैं।

%बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ% के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई है, जो विकसित भारतञ्च2047 के लिए हमारे सामूहिक मिशन को भी आगे बढ़ा रही है। इसी सफर में एक अहम पड़ाव पिछले वर्ष 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है।

अपनी साहसिक और अटल दृष्टि के साथ, हमने वर्ष 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है, ताकि हर बालिका और बालक सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें, अपनी शिक्षा जारी रख सकें और गर्व तथा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को आकार दे सकें। शुरू से ही, हमने %संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज% के नज़रिए को अपनाया है, लिहाज़ा हम मानते हैं कि इस चुनौती का हल महज़ नीतियों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामूहिक एकता की ज़रुरत है, जिसमें परिवार, समुदाय, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, संस्थान और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने और हर बच्चे की आकांक्षाओं की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़े हों। हमारे साझा संकल्प के एक शक्तिशाली प्रतिबिंब के रूप में, गाँवों और कस्बों के करोड़ों लोग बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लेने के लिए आगे भी आए हैं।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए %पूरी सरकार% एकजुट

बाल विवाह हमारे देश में पीढ़ियों से चली आ रही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह अक्सर उन समुदायों में दिखती है, जहाँ शिक्षा, संसाधनों और जागरूकता की सीमित पहुँच है। अभाव और असमान अवसरों के कारण पैदा हुई ये कमियाँ, इस प्रथा को जारी रखने में मदद करती हैं, जिससे अनगिनत बच्चे अपने उज्ज्वल भविष्य को साकार करने से वंचित रह जाते हैं।

वर्तमान में बेहतरी के लिए प्रयास- मोदी सरकार के तहत, हम उन जड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इस प्रथा को पोषित किया था। स्पष्ट नीतिगत दिशा, विचार विमर्श कर तैयार की गई योजनाओं और शासन में समुदायों के नए विश्वास के साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन परिस्थितियों को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिनके कारण बाल विवाह की प्रथा अब तक जारी रही। आज हम जो प्रगति देख रहे हैं, वह सुनियोजित ढंग से तैयार की गई योजनाओं की वजह से हैं, जिनके तहत महिलाएं और बच्चे राष्ट्रीय विकास के केंद्र में हैं।

हमारी नीतियां और पहल, संवेदनशील कारणों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर अधिकार, देश के सबसे दूरस्थ गाँव और बस्तियों में सबसे कमजोर बच्चे के जीवन पर सकारात्मक असर डालते हुए अंतिम छोर तक पहुँचे। सरकार की हर योजना महिलाओं और बच्चों को जोखिम के हर चरण में सहारा देने के लिए तैयार की गई है, ताकि अजन्मे बच्चे से लेकर किशोरी तक, उनके जीवन के हर चरण की सुरक्षा, प्राथमिकता और सशक्तिकरण हो।

पोषण ट्रैकर और पोषण भी पढ़ाई भी से लेकर समग्र शिक्षा अभियान तक, और राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम से लेकर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना तक, हर पहल एक सुरक्षा कवच और हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान भविष्य की ओर एक मार्ग के रूप में कार्य करती है।

समावेशन के उत्प्रेरक के रूप में तकनीक की मदद से, मंत्रालय का प्रमुख डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, पोषण ट्रैकर, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्तनपान कराने वाली माताओं, छह साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरियों से सहजता से जोड़ता है। इसने देश भर में 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एक मज़बूत सुरक्षा तंत्र तैयार कर दिया है। इस डिजिटल सक्षमता के साथ पोषण भी पढ़ाई भी, एक बदलावकारी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पहल के रूप में तैयार हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पूर्व–प्राथमिक बच्चे को समग्र, उच्च–गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन मिले, जो आजीवन सीखने की भावना की नींव रखता है।

हमारी नीतियाँ न केवल इरादे, बल्कि ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई को भी दर्शाती हैं। निरंतर बजटीय प्रतिबद्धताओं और लक्षित निवेशों में सुधारों को शामिल करते हुए, मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बाल विवाह जैसी गंभीर समस्याओं से बच्चों की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिसके लिए केवल 2025–26 के लिए 1,827 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण स्कूल न छोड़े, जो बाल विवाह के सबसे अहम कारणों में से एक है। इस बीच, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली युवतियों को ज़रुरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने युवाओं को उद्योग–संबंधित कौशल से लैस करके, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और मान्यता प्राप्त सरकारी प्रमाणन प्रदान करके इस सुरक्षा कवच को और मज़बूत किया है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री–दक्ष योजना, हाशिए पर पड़े समुदायों, खासकर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाती है, जो बाल विवाह के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। उन्हें कौशल और अवसरों का लाभ देकर, हम समृद्ध और स्वतंत्र जीवन के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं।

प्रभाव- बाल विवाह मुक्त भारत बनने के और नज़दीक

कुछ साल पहले तक, बाल विवाह को समाप्त करने का विचार दूर की कौड़ी, यहाँ तक कि असंभव नज़र आता था। लेकिन भारत ने इसके विपरीत साबित कर दिया है। स्पष्ट नीतियों, निरंतर कार्रवाई, केंद्रित जमीनी प्रयासों और मापयोग्य प्रगति के ज़रिए, हमने उस धारणा को चुनौती दी है और दिखाया है कि बदलाव न केवल मुमकिन है, बल्कि पहले से ही उसके प्रयास जारी हैं। यह अभूतपूर्व बदलाव हज़ारों छोटी–बड़ी, सशक्त कोशिशों का नतीजा है। हमारे बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) इस मिशन की रीढ़ बनकर उभरे हैं। पिछले एक साल में ही, हमने देश भर में 37,000 से ज़्यादा सीएमपीओ नियुक्त करके अपनी अग्रिम पंक्ति को मज़बूत किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाकर, पंचायतों को सशक्त बनाकर और जिला प्रशासन को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी देकर, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सबसे वंचित परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, बच्चों को वापस स्कूल लाया जाए और समुदायों को बाल विवाह के गंभीर उल्लंघन के बारे में जागरूक किया जाए। अब तक, हमने 6,30,000 से ज़्यादा, स्कूल न जाने वाली लड़कियों की पहचान की है और उन्हें कक्षाओं में फिर से दाखिला दिलाया है। चुप्पी से लेकर शिकायत तक, सामाजिक कलंक से लेकर समर्थन तक–भारत ने चुना बदलाव का रास्ता- आज, हम इस समस्या का हल अधिक सटीकता, पारदर्शिता और प्रभाव के साथ निकालने के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति की मदद ले रहे हैं। सार्वजनिक रूप से सुलभ, केंद्रीकृत मंच, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, इस प्रगति का प्रतीक है, जो देश भर के बाल विवाह निषेध अधिकारियों की जानकारी एक साथ लाता है, मामलों की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है, और हितधारकों और नागरिकों के बीच जागरूकता को मज़बूत करता है।

पहली बार, बाल–विवाह–मुक्त भारत का सपना एक एकीकृत राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित हुआ है। भारत सरकार का प्रत्येक अंग और समाज का प्रत्येक वर्ग इस साझा उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम आज न केवल अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि विकसित भारत की एक मज़बूत, आत्मविश्वासी और सशक्त नींव भी रख रहे हैं।

जैसे–जैसे भारत बाल विवाह के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच रहा है, हम दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं, कि कैसे शासन और समुदाय मिलकर हर बच्चे की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं और बाल विवाह के वैश्विक संकट को तत्काल और निश्चित रूप से खत्म कर सकते हैं। आखिरकार, ये बच्चे ही उस विकसित भारत के पथप्रदर्शक और सच्चे %सारथी% हैं, जिसका निर्माण हम सभी करना चाहते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय, जालंधर ने मोगा में 'वार्तालाप' मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया

उपायुक्त मोगा श्री सागर सेतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, ' भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, नीतियों और पहलों की महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका' विषय पर हुई चर्चा

मोगा, 27 नवंबर–(रमन कुमार) चंडीगढ़ की जालंधर शाखा द्वारा वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित 'वार्तालाप' मीडिया कार्यशाला का मोगा में आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से मोगा के पत्रकार शामिल हुए। इस मीडिया कार्यशाला में 'भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, नीतियों और पहलों की महिला सशक्तिकरण में भूमिका' विषय पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त मोगा, श्री सागर सेतिया, आईएएस ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से की गई।

मीडिया एवं संचार अधिकारी, डॉ. विक्रम सिंह ने कार्यशाला में पहुँचे सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों की भूमिका के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीआईबी मंत्रालय का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों/योजनाओं और पहलों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाने के लिए पीआईबी और मीडिया के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से 'वार्तालाप' का आयोजन किया जाता है। उपायुक्त मोगा, श्री सागर सेतिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की देश की प्रगति में विशेष भूमिका है और यदि महिलाएँ सशक्त होंगी तो हमारा देश और अधिक उन्नति करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कई ऐसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिन्होंने देश की महिलाओं को सशक्त करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और प्रयास है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुँचे। इसके लिए मीडिया के साथ सरकार का समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 'वार्तालाप' जैसे कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच संवाद स्थापित करने में अहम योगदान देते हैं, जिसका लाभ आम जनता तक पहुँचता है। मीडिया के माध्यम से लोग यह जान पाते हैं कि सरकार उनके लिए कौन–कौन सी योजनाएँ चला रही है और उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मोगा की जिला परिवार कल्याण अधिकारी, डॉ. रीतू जैन ने कहा कि यदि देश के लोग स्वस्थ होंगे तो वे देश की प्रगति में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार की कई योजनाएँ विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। उन्होंने कहा कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। शिक्षा विभाग मोगा की जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), श्रीमती मंजू भारद्वाज ने कहा कि भारत सरकार देश की बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष की सभी बेटियों सहित सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही मिड–डे मील योजना के तहत बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन दिया जा रहा है और रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से बेटियों को आत्म–सुरक्षा की शिक्षा दी जा रही है।

इस अवसर पर कृषि अधिकारी, मोगा, डॉ. सुखराज कौर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विभाग में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दे रही है, जिससे किसानी और महिला सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि नैनो ड्रोन दीदी पहल के तहत जिला मोगा में चार महिलाएँ ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करने के कार्य में मिसाल बनी हैं।

ज़िला रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण अधिकारी, मोगा, श्रीमती डिंपल ठाकुर ने कहा कि विभाग द्वारा कई ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनसे महिलाएँ अपनी कला के माध्यम से सशक्त हो रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। कौशल विकास मिशन की ब्लॉक मिशन मैनेजर, श्रीमती मनप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में महिलाओं की विशेष भूमिका के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. सुखदीप सिंह, सूचना सहायक ने पत्रकारों, मुख्य अतिथि और वक्ताओं का धन्यवाद किया। कार्यशाला के अंत में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस-विजीलैंस ब्यूरो द्वारा 5 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में ए.एस.आई. गिरफ्तार

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत थाना भोगपुर, जिला जालंधर में तैनात ए.एस.आई. जसविंदर सिंह को 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज यहां यह जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर जालंधर शहर के मकसूदां निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई है।

जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता को थाना भोगपुर में दर्ज एक मामले में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। उस मामले के जांच अधिकारी ए.एस.आई. जसविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार न करने, पिस्तौल की बरामदगी न दिखाने और पहले से गिरफ्तार आरोपी सुरजीत सिंह के लिए आगे पुलिस रिमांड न मांगने के बदले एस.एच.ओ. राजेश कुमार के नाम पर 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने वह बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें आरोपी ए.एस.आई. 5 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता की गुजारिश पर रिश्वत की राशि को कम करके 2 लाख रुपये कर दिया गया था। जांच के दौरान एस.एच.ओ. राजेश कुमार द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आगे की जांच में एस.एच.ओ. की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजीलैंस ब्यूरो थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री की ओर से जापान के साथ प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की वकालत

मनदीप कौर

उन्नत निर्माण, गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं की खोज

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जापान के साथ उन्नत निर्माण, गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की वकालत की। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ जापान के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्चुअल विचार–विमर्श किया, जिसमें जापानी दूतावास, जेट्रो, जे.सी.सी.आई.आई. और भारत भर में कार्यरत 25 से अधिक प्रमुख जापानी कंपनियां जैसे पैनासोनिक, सुमितोमो, निप्पॉन, एनईसी, टोयोटा आदि शामिल थी। यह विचार–विमर्श 13 से 15 मार्च 2026 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आई.एस.बी.), मोहाली में आयोजित होने वाले 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट से पहले पंजाब की अंतरराष्ट्रीय पहुंच का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्वेस्ट पंजाब ने राज्य के आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ एक ही प्राधिकरण के तहत कई विभागों की क्षमताओं को एकीकृत करने वाले अनूठे इन्वेस्ट पंजाब यूनिफाइड रेगुलेटरी मॉडल को प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब वह भूमि है जो साहस, लचीलापन, कड़ी मेहनत, उद्यमशीलता, रचनात्मकता और सामुदायिक साझेदारी के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा भारत के विकास में, विशेष रूप से देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब आधुनिक उद्योग, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग के मोर्चे पर अग्रणी केंद्र बनने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने मुख्य संबोधन में जापानी उद्योग के साथ पंजाब के मजबूत और बढ़ते संबंधों पर जोर दिया और जापानी कंपनियों को पंजाब के औद्योगिक परिवर्तन के अगले चरण का हिस्सा बनने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और जापान विश्वास, अनुशासन और दीर्घकालिक साझेदारी की मूल्यों को साझा करते हैं, जो राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जापानी कंपनियों ने पंजाब में पहले से ही मजबूत पकड़ बना ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ–साथ निवेशकों के लिए स्थिर और विश्वसनीय वातावरण सुनिश्चित करना है। जापानी उद्योग के साथ पंजाब की साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ये संबंध पहले से ही मजबूत हैं और नई दिशाओं की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापान की कई प्रसिद्ध कंपनियों ने पंजाब में अपना भरोसा दिखाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब के ऑटोमोटिव और विनिर्माण क्षेत्र में माज़दा, सुमितोमो, एसएमएल इसुज़ु, यानमार, आइची स्टील और गुनमा सीको ने अपने पैर पसार लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैकेजिंग और औद्योगिक उत्पादों में टोपन और ओजी होल्डिंग्स ने मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि रसायन और पेंट में कंसाई नेरोलैक और निसान केमिकल ने सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कृषि और मशीनरी में यानमार एग्रीकल्चर मशीनरी और क्लास इंडिया ने पंजाब में अपना भरोसा दिखाया है। रिटेल और उपभोक्ता उत्पादों में यूनिक्लो ने जापानी गुणवत्ता हमारे लोगों तक पहुंचाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में मित्सुई एंड कंपनी हमारे हरित दृष्टिकोण में योगदान दे रही है और यह साझेदारी स्थिरता, कौशल और विकास के प्रति पंजाब की प्रतिबद्धता में जापानी निवेशकों द्वारा दिखाए गए भरोसे को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार पंजाब की औद्योगिक क्षमताओं पर प्रकाश डाल रही है, सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज कर रही है और जापानी उद्योग के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब आज भारत के सबसे अधिक कारोबार–अनुकूल राज्यों में से एक है और भारत सरकार ने 2024 की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) रैंकिंग में पंजाब को प्रथम स्थान दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की कारोबार में सुगमता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का दृष्टिकोण सरल और स्पष्ट है – नीतिगत स्थिरता, त्वरित निर्णय लेना और निवेशकों के समय व विश्वास का सम्मान करने वाली शासन प्रणाली लाकर पंजाब को वैश्विक उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण साझेदारी और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने, उनकी जरूरतों को समझने और यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि सरकार विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

पंजाब ने जी.सी.सी. और सी.आई.एस. राजदूतों के साथ गोलमेज़ बैठकों द्वारा वैश्विक साझेदारी के ताने-बाने किए मजबूत

राजदूतों ने राज्य की सक्रिय पहल की सराहना की, निवेश, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर हुई विस्तृत चर्चा

पंकज

चंडीगढ़/नई दिल्ली, 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट (पी पी आई एस)–2026 से पहले की अंतरराष्ट्रीय पहल के तहत पंजाब सरकार ने आज नई दिल्ली में खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) देशों और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सी आई एस) क्षेत्र के राजदूतों के साथ दो गोलमेज़ बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने की। इन बैठकों में विभिन्न देशों के राजदूतों, वरिष्ठ कूटनीतिक प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रालय (एम ई ए) के अधिकारियों तथा पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। दोनों बैठकें श्री के.के. यादव, आई ए एस, प्रशासकीय सचिव, निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वागत भाषण से प्रारंभ हुईं। इसके बाद 卐एडवांटेज पंजाब卐 प्रस्तुति दी गई, जिसमें राज्य के सशक्त औद्योगिक वातावरण, निवेश–तैयार बुनियादी ढांचे, नीतिगत सुधारों तथा कृषि, कृषि–तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण में उभरते अवसरों का विस्तृत विवरण दिया गया। जी सी सी गोलमेज़ बैठक में कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के राजदूतों ने भाग लिया, जो पंजाब के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए जी सी सी ब्लॉक की

सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजदूतों ने पंजाब की प्रस्तुति की सराहना की और कहा कि विश्वस्तरीय बंदरगाहों, मजबूत लॉजिस्टिक्स प्रणालियों तथा अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक संपर्क के कारण जी सी सी क्षेत्र पंजाब और भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात द्वार बन सकता है। उन्होंने पंजाब की विनिर्माण क्षमता, कुशल मानव संसाधन, उद्यमशीलता और जी सी सी की आर्थिक विविधता के बीच मजबूती से जुड़ने वाली समानताओं का उल्लेख किया। सी आई एस गोलमेज़ बैठक में कज़ाकिस्तान, रूस, आर्मेनिया और बेलारूस के राजदूतों ने हिस्सा लिया। इन देशों ने पंजाब के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने में गहरी रुचि दिखाई। कज़ाकिस्तान के राजदूत ने शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति, तथा व्यापार और निर्यात को सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभ बताते हुए पंजाब की मजबूत अकादमिक संस्थाओं, आधुनिक कृषि पद्धतियों और समृद्ध पर्यटन संभावनाओं की प्रशंसा की। रूसी संघ के राजदूत ने पंजाब के साथ कृषि व्यापार–विशेषकर चावल और टमाटर उत्पादों–को बढ़ाने की विशाल संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे, पेट्रो–केमिकल, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एयरोस्पेस, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में सहयोग की संभावनाएं भी उजागर कीं। उन्होंने भारत–रूस राष्ट्रीय स्तर सहयोग मंच में पंजाब की भागीदारी का स्वागत किया। आर्मेनिया के राजदूत ने सी आई एस देशों तक पंजाब की सक्रिय पहुंच की प्रशंसा की और कृषि–तकनीक, डेयरी, आईटी सेवाओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा में साझेदारी की इच्छा जताई। उन्होंने पर्यटन प्रबंधन, कौशल विकास, लोगों के बीच संपर्क, वार्षिक सांस्कृतिक त्योहारों तथा विश्वविद्यालय–स्तरीय सहयोग की महत्ता पर भी बल दिया। बेलारूस के राजदूत ने पंजाब सरकार को सी आई एस क्षेत्र के साथ सीधे सहयोग की पहल शुरू करने के लिए बधाई दी और कृषि शिक्षा तथा कृषि मशीनरी निर्माण में बेलारूस की विशेषज्ञता का उल्लेख किया। उन्होंने पंजाब के उद्योग जगत और सरकार को जून 2026 में होने वाली बेलारूस की वार्षिक कृषि प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण दिया, जो बी 2बी मीटिंग और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए उपयुक्त मंच है। अपने संबोधन में मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब के प्रगतिशील सुधारों–जैसे बिजनेस राइट्स एक्ट और उन्नत फास्ट–ट्रैक पंजाब सिंगल–विंडो सिस्टम–पर प्रकाश डाला, जो आज भारत का सबसे आधुनिक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म है। उन्होंने जी सी सी और सी आई एस देशों के प्रतिनिधियों को पंजाब को विनिर्माण और सेवाओं के लिए पहली पसंद बनाने तथा इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से क्षेत्र–विशेष सहयोग को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जी सी सी और सी आई एस देशों के राजदूतों तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 में शामिल होने और कृषि, कृषि–तकनीक, डेयरी, आईटी सेवाएं, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश अवसरों का लाभ उठाने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सभी देशों के प्रतिनिधियों को पंजाब के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थलों का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया तथा यह भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार निवेश–अनुकूल नीतियां, समयबद्ध अनुमतियाँ और वैश्विक स्तर का प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बैठकों में भाग लिया और पंजाब की लक्ष्यित तथा क्षेत्र–केंद्रित अंतरराष्ट्रीय पहल रणनीति की सराहना की। उन्होंने भारत की व्यापक आर्थिक कूटनीति में पंजाब के महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। जी सी सी और सी आई एस के सभी राजदूतों ने पहली बार इस स्वरूप में आयोजित पंजाब के अंतरराष्ट्रीय आउटरीच की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री स भगवंत मान का आभार व्यक्त किया तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों को सुगमता प्रदान करने, क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने और व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देने पर सहमति जताई। इन गोलमेज़ बैठकों का समापन इस सहमति के साथ हुआ कि दोनों पक्ष मार्च 2026 में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में जी सी सी और सी आई एस की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निकट सहयोग बनाए रखेंगे और तैयारियों को और तेज़ करेंगे।

पंजाब में मनरेगा की गड़बड़ियों की होगी जांच, केंद्र से भेजी जाएगी टीम–केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री आवास और आजीविका योजनाओं का त्वरित लाभ पंजाब को मिल रहा है, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 5 लाख बहनों के लिए विशेष पैकेज, बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मकानों पर अलग से सहायता, किसानों को मुफ्त कनक बीज के लिए 74 करोड़ रु. की स्वीकृति, बरसीम के 12,500 क्विंटल बीज वितरण की अलग व्यवस्था, मनरेगा में 100 से बढ़ाकर 150 दिन का रोजगार, पंजाब के लिए विशेष राहत, केंद्र सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है– शिवराज सिंह

जालंधर/नई दिल्ली, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब प्रवास के दौरान जालंधर में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और हितग्राहियों से संवाद किया। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक दल भेजा जाएगा। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि मनरेगा गरीबों और ग्रामीण मजदूरों की आजीविका से सीधे जुड़ी योजना है, इसलिए इसमें एक रुपये की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र की सभी योजनाओं का त्वरित लाभ पंजाब को दिया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सामान्यत: मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन पंजाब में बाढ़ के कारण फसलें खराब होने और खेतों में काम के अवसर घटने की आशंका को देखते हुए यहां विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए मनरेगा में रोजगार के दिन

बढ़ाकर 150 दिन किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की इस पहल को स्वीकार किया है और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंद मजदूरों को अधिक दिनों का रोजगार समय पर मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

साथ ही, श्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि पंजाब में मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें फर्जी जॉब कार्ड बनना, ठेकेदारों के माध्यम से काम कराया जाना, काम मांगने के बावजूद मजदूरों को रोजगार न मिलना और नहरों की सफाई जैसे कार्यों में बिना वास्तविक काम के भुगतान जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। उन्होंने साफ कहा कि मनरेगा की धनराशि ठेकेदारों या बिचौलियों के लिए नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए है, इसलिए ऐसे सभी मामलों की गहन जांच कर दोषियों को दंडित करना जरूरी है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में मनरेगा के लिए अब तक कुल 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करा चुकी है और इसी वित्त वर्ष में राज्य को 842 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जिन जिलों से शिकायतें आई हैं, वहां तत्काल जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, जबकि केंद्र की टीम भी मौके पर जाकर जांच–पड़ताल करेंगी, ताकि यदि कहीं मनरेगा का पैसा गलत हाथों में गया हो तो उसे रोका जा सके और गरीब मजदूरों को उनका पूरा हक दिलाया जा सके।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण सड़कों, पेयजल, आवास और आजीविका बढ़ाने वाली योजनाओं के जरिए गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। श्री चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत चल रहे आजीविका मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 5 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हाल की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इन बहनों के लिए विशेष पैकेज दिया गया है, ताकि वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से जारी रख सकें और आजीविका के साधन मजबूत कर सकें। श्री चौहान ने कहा कि विशेष सहायता से स्वयं सहायता समूहों की बहनों के छोटे–छोटे व्यवसाय और आजीविका से जुड़े काम पूरे हो सकेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाढ़ से प्रभावित परिवारों के मकानों पर समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले 14 हजार और बाद में 36 हजार मकानों की सूची केंद्र को भेजी, जिनमें से लगभग 30 हजार आवासों की स्वीकृति हो चुकी है, जबकि करीब 6 हजार स्वीकृतियां लंबित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाढ़ में जिन गरीब परिवारों के घर टूट गए हैं, उनके मकान राज्य द्वारा तुरंत स्वीकृत कर बनाए जाने चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के एक लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल लगभग 76 हजार की ही स्वीकृतियां राज्य द्वारा जारी हो पाई हैं। उन्होंने राज्य सरकार से स्पष्ट किया कि या तो शेष पात्र लाभार्थियों को तुरंत स्वीकृति दी जाए या यदि किसी मामले में अपात्रता है तो उसे समयबद्ध तरीके से दर्ज कर केंद्र को बताया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक पात्र गरीब परिवार का पक्का घर बनने से न रह जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में सहायता देने के लिए भी विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है, ताकि जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें शीघ्र राहत मिल सके।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों को बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को कनक के बीज मुफ्त में वितरित करने के लिए 74 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि बरसीम के बीज के लिए भी अलग बजट दिया गया है, ताकि लगभग 12,500 क्विंटल बीज का वितरण किया जा सके और बुवाई में किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि यह सहायता कोई एहसान नहीं, बल्कि पंजाब की जनता की विनम्र सेवा की भावना से दिया जा रहा सहयोग है।

श्री चौहान ने कहा कि कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, दोनों की ओर से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसान और ग्रामीण परिवार जल्दी सामान्य स्थिति में लौट सकें। आजीविका मिशन पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार लगातार पंजाब सरकार के साथ सहयोग कर रही है। स्वयं सहायता समूहों की क्षमता बढ़ाने, सस्ती ऋण सुविधा और मार्केट लिंक प्रदान करने के लिए भी केंद्र की विभिन्न योजनाओं को जोड़ा जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पंजाब के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और राज्य के किसानों, मजदूरों तथा ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए केंद्र की यह प्रतिबद्धता केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर चल रही योजनाओं और स्वीकृत आर्थिक पैकेजों में साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता की सेवा के इसी लक्ष्य के साथ वे बार–बार राज्य के दौरे पर आते रहेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की स्वयं समीक्षा करते रहेंगे। श्री चौहान ने जालंधर प्रवास के दौरान हुई बैठक के संदर्भ में उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयास से पंजाब के गांव आने वाले समय में और अधिक सक्षम और समृद्ध बनेंगे।

राकेश राठौर ने गुरु नानकपुरा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चिंतपूर्णी के लिए रवाना की बस

मनदीप कौर

जालंधर–गुरु नानकपुरा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सनी शर्मा एवं अध्यक्ष राजन शर्मा द्वारा माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने लिए मोहल्ला वासियों के लिए बस को मुख्य मेहमान भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं जालंधर के पूर्व में राकेश राठौर ने नारियल फोड़ कर रवाना किया गया। राकेश राठौर ने कहा कि माता चिंतपूर्णी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए सोसाइटी द्वारा की गई व्यवस्था सराहनीय है। उन्होंने सोसाइटी के सदस्यों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यात्रा को रवाना किया और कहा कि माता चिंतपूर्णी की कृपा सभी पर बनी रहे। राकेश राठौर ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से समाज में एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है। राकेश राठौर ने सोसाइटी के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि वे हमेशा समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में बढ़–चढ़कर कार्य करते रहते हैं। बस में सवार श्रद्धालुओं ने भी राकेश राठौर का आभार व्यक्त किया और माता चिंतपूर्णी की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा जिला जालंधर के पूर्व अध्यक्ष रमन पबी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सनी शर्मा, गुरु नानकपुरा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजन शर्मा भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीष विज, नितिन बहरोल, वे अन्य उपस्थित थे

पंजाब ने केंद्र से 250 करोड़ रुपये के मनरेगा फंड तुरंत जारी करने की मांग की

कहा, 3000 से अधिक खेल मैदान, 2800 नई आंगनवाड़ी इमारतें राज्य में ग्रामीण विकास को देंगी बढ़ावा

पंकज

जालंधर, – पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार के पास बकाया 250 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की जोरदार अपील की। केंद्रीय मंत्री के साथ समीक्षा बैठक के बाद जिला प्रशासकीय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री सौंद ने कहा कि मटीरियल कंपोनेंट के तहत रोके गए फंड के कारण पंजाब में इस महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है। मजदूरी में समानता की मांग करते हुए कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मनरेगा के तहत काम करने वाले राज मिस्त्रियों की मजदूरी में संशोधन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज मिस्त्री को 400 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जबकि पंजाब में राज मिस्त्री को केवल 346 रुपये मजदूरी दी जा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महंगाई और मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण इतनी कम मजदूरी पर कुशल मिस्त्री मिलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पंजाब की पहल पर प्रकाश डालते हुए श्री सौंद ने बताया कि राज्य देश में मनरेगा कर्मियों के लिए चेहरे की पहचान (फेस रिकॉग्निशन) और जियो–टैगिंग आधारित हाजिरी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट, जो वर्तमान में फतेहगढ़ साहिब में चल रहा है, जल्द ही सभी 23 जिलों में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप पिछली सरकारों के दौरान मनरेगा में अनियमितताओं से जुड़े 23 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों से 2 करोड़ रुपये भी वसूल किए गए है। श्री सौंद ने केंद्र सरकार से भारी बारिश से हुए नुकसान की सहायता के रूप में पहले घोषित 1600 करोड़ रुपये के बकाया बाढ़ राहत फंड जारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बार–बार याद दिलाने के बावजूद एक भी रुपया जारी नहीं किया गया, जो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ सौतेले मां जैसे व्यवहार को दर्शाता है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पंजाब सरकार की चल रही पहलों के बारे में जानकारी दी, जिसमें पूरे राज्य में 3,000 से अधिक खेल मैदानों का निर्माण और 2,800 से अधिक नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण शामिल है। उन्होंने दोहराया कि यह प्रोजेक्ट राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को बड़ा बल देंगे।

ऑडिट दिवस 2025-पंजाब के लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने में ऑडिट की भूमिका विषय पर आयोजित किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम

ऑडिट दिवस 2025 के उपलक्ष्य में, लेखा महानियंत्रक, पंजाब के कार्यालय ने विषय स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने में ऑडिट की भूमिका पर किया एक प्रमुख आयोजन

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), पंजाब ने ऑडिट दिवस 2025 के अवसर पर स्थानीय शासन में ऑडिट की भूमिका विषय पर महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़, में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने में ऑडिट की अहम भूमिका को रेखांकित करना था।

कार्यक्रम में श्री कुलतार सिंह संधवां, माननीय अध्यक्ष, पंजाब विधानसभा मुख्य अतिथि के रूप में तथा श्री पीपीएल बुध राम, विधायक बुधलाडा एवं पंचायती राज संस्थाओं की समिति के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। PRI और LB की समिति के अन्य सम्मानित सदस्य–कुलजीत सिंह

रंधावा, श्री अजीत पाल सिंह कोहली, श्रीमती जीवन ज्योत कौर, श्री हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों, श्री सुखविंदर सिंह कोटली, श्रीमती नीना मित्तल, श्री गुरलाल घनौर, श्री लाभ सिंह उगोके और श्री अशोक पराशर–भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। संगोष्ठी में पंजाब भर के सरपंचों, नगर निगम लुधियाना की मेयर श्रीमती इंदरजीत कौर, तथा स्थानीय सरकार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग और लोक निधि लेखा परीक्षक के वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अनुपालन से

सशक्तिकरण तक – स्थानीय शासन में ऑडिट की भूमिका विषय पर पैनल चर्चा रही। चर्चा में यह रेखांकित किया गया कि ऑडिट सुशासन का आधार स्तंभ है, जो वित्तीय अनुशासन, कानूनों का अनुपालन और सार्वजनिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मजबूत करने में ऑडिट की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि ग्रामीण विकास और शहरी निकायों के लिए आवंटित धन नागरिक कल्याण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग हो सके। संगोष्ठी ने विधायकों, लेखा परीक्षकों और जमीनी प्रतिनिधियों के बीच संवाद का मंच प्रदान किया, जिससे पारदर्शी और जवाबदेह शासन की साझा दृष्टि को बढ़ावा मिला। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि ऑडिट केवल वित्तीय प्रक्रिया नहीं है; यह लोकतांत्रिक शासन में आश्वासन और विश्वास निर्माण का उपकरण है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए, ऑडिट एक मार्गदर्शक उपकरण है–जो उन्हें संसाधनों का कुशल प्रबंधन, अंतराल की पहचान और सेवा वितरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करता है। ऑडिट केवल निगरानी नहीं है; यह सशक्तिकरण का साधन है। व्यवस्थित मूल्यांकन और रचनात्मक सिफारिशों के माध्यम से, ऑडिट स्थानीय निकायों को सूचित निर्णय लेने, वित्तीय अनुशासन में सुधार और सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह शासन को सिर्फ व्यय की निगरानी से प्रदर्शन आश्वासन में बदल देता है, जिससे स्थानीय संस्थाएं विकास की सच्ची एजेंट बनती हैं। प्रधान महालेखाकार सुश्री नाज़ली जे. शाईन ने मीडिया को बताया कि यह संगोष्ठी सहयोगात्मक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विधायी निगरानी को पेशेवर ऑडिट प्रथाओं के साथ जोड़ती है, ताकि नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके। IA&AD के वरिष्ठ अधिकारीऔर कार्यालय के सभी कर्मचारी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल हुए।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया

श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं; गुरु साहिब का जीवन, बलिदान और चरित्र प्रेरणा का एक गहन स्रोत है; मुगल आक्रांताओं के उस काल में, गुरु साहिब ने साहस और वीरता के आदर्श स्थापित किए–प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 26 नवंबर–– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन भारत की विरासत का एक अद्भुत संगम है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सुबह वे रामायण की नगरी अयोध्या में थे और अब गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित संतों और सम्मानित संगत की उपस्थिति का आभार व्यक्त किया और सभी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

श्री मोदी ने 5–6 वर्ष पहले घटित एक और अद्भुत संयोग का समरण करते हुए बताया कि 9 नवंबर 2019 को, जब सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया, वे करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस दिन वे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने और करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी की प्रार्थनाएँ उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाकर स्वीकार कर ली गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब, जब अयोध्या में धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है, उन्हें एक बार फिर सिख संगत से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है।

श्री मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले ही कुरुक्षेत्र की धरती पर %पाञ्चजन्य स्मारक% का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा को सर्वोच्च कर्तव्य बताया था। श्री मोदी ने भगवान कृष्ण की वाणी का स्मरण करते हुए कहा कि सत्य के मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्य के लिए प्राण त्यागना सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस धर्म का पालन किया। श्री मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर, भारत सरकार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि सरकार इसी प्रकार गुरु परंपरा की सेवा करती रहे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पवित्र यात्राओं के दौरान इस भूमि पर आए थे। उन्होंने स्मरण किया कि जब नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी, इस पवित्र भूमि पर आए, तो उन्होंने गहन तपस्या और निडर साहस की गहरी छाप छोड़ी।

श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा, 卐श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ हैं और उनका जीवन, बलिदान और चरित्र प्रेरणा का एक महान स्रोत है।卐 उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुगल आक्रमणों के दौरान, गुरु साहिब ने बहादुरी का आदर्श स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से पहले, मुगल आक्रांताओं द्वारा कश्मीरी हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था। इस संकट की घड़ी में, उत्पीड़ितों के एक समूह ने गुरु साहिब से सहायता मांगी। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि गुरु साहिब ने उनसे कहा था कि वे औरंगज़ेब को स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि श्री गुरु तेग बहादुर स्वयं इस्लाम स्वीकार करते हैं, तो वे भी इस्लाम धर्म अपना लेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि ये शब्द श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जिसका डर था, वही हुआ। क्रूर औरंगज़ेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहिब ने स्वयं दिल्ली जाने का निर्णय घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभनों से लुभाने की कोशिश की, फिर भी श्री गुरु तेग बहादुर अडिग रहे और अपनी आस्था और सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनके संकल्प को तोड़ने और उन्हें उनके मार्ग से विचलित करने के लिए, मुगलों ने उनकी आँखों के सामने उनके तीन साथियों – भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मति दास जी को बेरहमी से मार डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि तब भी गुरु साहिब अडिग रहे, उनका दृढ़ संकल्प अटूट रहा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गुरु साहिब ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और गहन ध्यान की अवस्था में आस्था की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुगल यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुरु महाराज के पवित्र शीश का अपमान करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाई जैता जी ने अपनी वीरता से गुरु का शीश आनंदपुर साहिब तक पहुँचाया। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्दों को याद किया, जिसका अर्थ है कि आस्था के पवित्र तिलक की रक्षा की जाए, लोगों की आस्था को उत्पीड़न से बचाया जाए और इसके लिए गुरु साहिब ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि आज गुरु साहिब के बलिदान की भूमि दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के रूप में प्रेरणा का एक जीवंत स्थल है, श्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आनंदपुर साहिब का तीर्थस्थल हमारी राष्ट्रीय चेतना का शक्ति केंद्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का जो स्वरूप शेष है, वह गुरु साहिब जैसे युगदृष्टा व्यक्तियों के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस सर्वोच्च बलिदान के कारण ही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को %हिंद की चादर% के रूप में सम्मानित किया जाता है।

श्री मोदी ने कहा, 卐हमारे गुरुओं की परंपरा राष्ट्र के चरित्र, संस्कृति और मूल भावना का आधार है।卐 उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने इन पवित्र परंपराओं और प्रत्येक सिख उत्सव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के पर्व के रूप में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों ने अपनी-अपनी आस्थाओं, परंपराओं और विश्वासों से ऊपर उठकर इन समारोहों में भाग लिया है।

इस बात पर जोर देते हुए कि उनकी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को सबसे भव्य और दिव्य रूप देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में ऐसे कई अवसर आए हैं जब वे व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बने हैं। प्रधानमंत्री ने याद किया कि कुछ समय पहले, जब गुरु ग्रंथ साहिब के तीन मूल स्वरूप अफगानिस्तान से भारत पहुंचे, तो यह प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का क्षण था।

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार ने गुरुओं के प्रत्येक तीर्थ स्थल को आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया है, श्री मोदी ने कहा कि चाहे वह करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना का निर्माण करना हो, या आनंदपुर साहिब में विरासत–ए–खालसा संग्रहालय का विस्तार करना हो, ये सभी कार्य गुरुओं की गौरवशाली परंपरा को मार्गदर्शक आदर्श मानकर पूरी निष्ठा के साथ किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी जानते हैं कि मुगलों ने बहादुर साहिबज़ादों के साथ भी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि साहिबज़ादों ने स्वयं को ज़िंदा ईंटों पर चिनवाया जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य या आस्था के मार्ग को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं आदर्शों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है ताकि सेवा, साहस और सच्चाई के आदर्श नई पीढ़ी की सोच का आधार बनें।

प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी ने %जोड़ा साहिब% के पवित्र दर्शन अवश्य किए होंगे। उन्होंने स्मरण किया कि जब पहली बार उनके कैबिनेट सहयोगी और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके साथ इन महत्वपूर्ण अवशेषों पर चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया था कि उनके परिवार ने गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र %जोड़ा साहिब% को लगभग तीन सौ वर्षों तक संरक्षित रखा था। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब यह पवित्र धरोहर देश और दुनिया भर के सिख समुदाय को समर्पित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके बाद, पवित्र %जोड़ा साहिब% का पूरे सम्मान और गरिमा के साथ वैज्ञानिक परीक्षण किया गया ताकि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पवित्र %जोड़ा साहिब% को तख्त श्री पटना साहिब को समर्पित करने का सामूहिक निर्णय लिया गया, जहाँ गुरु महाराज ने अपने बचपन का एक महत्वपूर्ण समय बिताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने, एक पवित्र यात्रा के अंतर्गत, पवित्र %जोड़ा साहिब% को दिल्ली से पटना साहिब ले जाया गया था, और वहाँ उन्हें भी उनके समक्ष शीश झुकाने का अवसर मिला था। उन्होंने इसे गुरुओं की विशेष कृपा माना कि उन्हें इस पवित्र विरासत की सेवा, समर्पण और उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

यह देखते हुए कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की स्मृति हमें सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी विशाल, उदार और मानवता–केंद्रित रही है, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुरु साहिब जी ने अपने जीवन के माध्यम से सरबत दा भला के मंत्र को चरितार्थ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह अवसर न केवल इन स्मृतियों और सीखों का सम्मान करने का अवसर है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। उन्होंने गुरु साहिब की शिक्षाओं को याद किया,

जिसका अर्थ है कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा साधक है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसी प्रेरणा से हमें हर चुनौती पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और अपने राष्ट्र को आगे ले जाना चाहिए, जिससे भारत विकसित बने। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें न तो किसी से डरना चाहिए और न ही किसी के डर में जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही निडरता समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाती है और आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत दुनिया से भाईचारे की बात करता है और साथ ही अपनी सीमाओं की रक्षा भी करता है। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि नया भारत आतंकवाद से न डरता है, न रुकता है और न ही उसके आगे झुकता है। उन्होंने कहा कि आज का भारत पूरी शक्ति, साहस और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर वह समाज और युवाओं से जुड़े एक ऐसे विषय पर बोलना चाहते हैं जो गुरु साहिब के लिए भी चिंता का विषय था – नशा और नशीले पदार्थों का मुद्दा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नशे की लत ने कई युवाओं के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यह समाज और परिवारों के लिए भी एक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शिक्षाएँ प्रेरणा और समाधान दोनों का काम करती हैं। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जब गुरु साहिब ने आनंदपुर साहिब से अपनी यात्रा शुरू की थी, तो उन्होंने अनेक गाँवों को संगत से जोड़ा, उनकी भक्ति और आस्था का विस्तार किया और साथ ही समाज के आचरण में भी बदलाव लाया। उन्होंने कहा कि इन गाँवों के लोगों ने सभी प्रकार के नशे की लत को त्याग दिया और अपना भविष्य गुरु साहिब के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गुरु महाराज के दिखाए मार्ग पर चलकर, यदि समाज, परिवार और युवा मिलकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ें, तो इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया

श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं; गुरु साहिब का जीवन, बलिदान और चरित्र प्रेरणा का एक गहन स्रोत है; मुगल आक्रांताओं के उस काल में, गुरु साहिब ने साहस और वीरता के आदर्श स्थापित किए- प्रधानमंत्री

हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है- प्रधानमंत्री मोदी

कुछ समय पहले, जब गुरु ग्रंथ साहिब के तीन मूल स्वरूप अफगानिस्तान से भारत पहुँचे, तो यह प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था– प्रधानमंत्री

हमारी सरकार ने गुरुओं के प्रत्येक पवित्र स्थल को आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया है, चाहे वह करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना का निर्माण करना हो, या आनंदपुर साहिब में विरासत–ए–खालसा संग्रहालय का विस्तार करना हो, और गुरुओं की गौरवशाली परंपरा से प्रेरणा लेते हुए, इन सभी प्रयासों को पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयस किया है- प्रधानमंत्री मोदी

हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की हर हद पार कर दी थी। साहिबजादों ने स्वयं को जिंदा ईंटों पर चिनवाया जाना स्वीकार किया, फिर भी अपने कर्तव्य या आस्था के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। इन्हीं आदर्शों के सम्मान में, अब हम प्रत्येक वार्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं- प्रधानमंत्री मोदी

पिछले महीने, एक पवित्र यात्रा के हिस्से के रूप में, गुरु महाराज के पूज्य जोड़ा साहिब को दिल्ली से पटना साहिब ले जाया गया। वहाँ, मुझे भी इन पवित्र जोड़ा साहिब के समक्ष शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने, स्वयं को समर्पित करने और इस पवित्र विरासत से जुड़ने का यह अवसर प्रदान किया– प्रधानमंत्री मोदी

नशे की आदत ने हमारे कई युवाओं के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यह समाज और परिवारों की भी लड़ाई है– प्रधानमंत्री